राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-292 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत की सीमा में घुसीं बांग्लादेशी नौकाएं

■ तटरक्षक बल ने 35 मछुआरों को किया गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने बीते दिन भारतीय समुद्री सीमा में अवैध रूप से घुसने के आरोप में 35 बांग्लादेशी मछुआरों को उनकी दो नावों के साथ हिरासत में ले लिया। कल सुबह भारतीय कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में दो संदिग्ध नावों को देखा और तुरंत उन्हें पकड़कर फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर ले जाया गया। कोस्ट गार्ड ने उन्हें फ्रेजरगंज कोस्टल पुलिस स्टेशन में पुलिस को सौंप दिया, जहां उन्हें अवैध रूप से घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मछुआरों से अभी पूछताछ की जा रही है और उन्हें आज दोपहर काकद्वीप कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले दो महीनों में, भारतीय कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में कई बांग्लादेशी ट्रॉलरों को पकड़ा है इस बीच, दोनों ट्रॉलर के नाम 'सबिना-1' और 'रूपोशी सुल्ताना' हैं। सबिना-1 में 11 और रूपोशी सुल्ताना में 24 बांग्लादेशी मछुआरे सवार थे। इससे पहले, 15 दिसंबर को भारतीय समुद्री सीमा में घुसने के बाद, बांग्लादेश नेवी के एक जहाज की टक्कर दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप के मछुआरों की एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर से हो गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख

■ कई बार याचिका डालने वाले 'सीरियल लिटिगेंट' पर 50 हजार जुमार्ना

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक सीरियल लिटिगेंट पर 50 हजार रुपये का जुमार्ना लगाया। यह व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में संपत्तियों के गैरकानूनी निर्माण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर कर चुका था, लेकिन बाद में उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। यह मामला तब सामने आया जब जस्टिस मिनी पुष्करना आरके पुरम क्षेत्र में संपत्ति के गैरकानूनी निर्माण के खिलाफ उसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर पांचवीं रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। उन्होंने नोट किया कि याचिकाकर्ता बार-बार याचिकाएं दायर कर रहा है, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहा। दो दिसंबर के आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक सीरियल लिटिगेंट है और उसने उक्त क्षेत्र में स्थित कई संपत्तियों के खिलाफ विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाएं दायर करने के बाद याचिकाकर्ता उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहा। पूर्व के आदेशों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति 'छिपे हुए उद्देश्यों' के लिए कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता का याचिकाएं दायर करना और उन्हें आगे न बढ़ाना, विश्वास को बढ़ावा नहीं देता और स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाएं स्वार्थी और असंगत उद्देश्यों के लिए दायर की गई हैं।

कैंची-धाम के पास खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 3 की मौत

6 गंभीर, बरेली से नैनीताल घूमने आए थे, झपकी आने से हुआ हादसा

एजेंसी

नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल में गुरुवार को पर्यटकों से भरी यूपी नंबर की स्कॉर्पियो 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। जिसमें गाड़ी चला रहे युवक की मां-पत्नी और साली की मौत हो गई है। जबकि कार में सवार अन्य 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भवाली पुलिस ने तीनों महिलाओं की मौत की पुष्टि करते हुए बताया है कि हादसा भवाली-अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर सुबह साढ़े 9 बजे के आसपास हुआ है। जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ। हादसे के बाद राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थानीय लोगों ने साथ मिलकर गाड़ी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सीएचसी सेंटर भेजा गया, कुछ घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया है। सभी घायल यूपी और गुजरात के रहने वाले हैं। ये लोग सुबह कैंची धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन धाम से करीब 5 किलोमीटर पहले ही हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक कार में सवार सभी लोग आपस में रिश्तेदार थे। भवाली पुलिस ने बताया कि हादसा भवाली से 3 किलोमीटर आगे निगलट के पास कैंची मंदिर से 5 किलोमीटर पहले हुआ। कार में 9 लोग सवार थे,

जिसमें से 3 की मौत हो गई है और 6 की हालत गंभीर है।स्कॉर्पियो सेफ्टी बैरियर को तोड़ते हुए 200 फीट गहरी खाई में गिरी है। कार नदी में जाकर गिरी है, जहां पर पास में ही श्मशान घाट है। स्कॉर्पियो का नंबर UP 25DZ 4653 है। अभी गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। मृतकों की पहचान गंगा देवी (55) पत्नी भूप राम, बृजेश कुमारी (26) पत्नी राहुल पटेल निवासीगण ग्राम चावण पोस्ट मुड़िया थाना इज्जतनगर बरेली, और नैंसी गंगवार (24) पुत्री जयपाल सिंह गंगवार निवासी पीलीभीत बरेली के तौर पर हुई है। वहीं घायलों की पहचान ऋषि पटेल उर्फ यूवी (7) पुत्र राहुल पटेल, स्वाति (20) पत्नी भूप राम, अक्षय (20) पुत्र ओमेंद्र सिंह, राहुल पटेल (35) पुत्र भूप राम निवासीगण ग्राम चावण पोस्ट मुड़िया थाना इज्जतनगर बरेली, करन उर्फ सोनू (25)

वीबी-जी राम जी' बिल लोकसभा में पास: विपक्ष ने कागज फाड़कर फेंके

शिवराज बोले: कांग्रेस ने चुनावी फायदे के लिए नरेगा में महात्मा गांधी जोड़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VB-G Ram G पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा का नाम पहले पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया। वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए। बापू याद आए। तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी। इसके बाद सदन में 'VB-जी राम जी बिल' बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला।

इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और VB-G-RAM-G बिल वापस लेने के नारे लगाए। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में VB-G-RAM-G बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:35 बजे तक चली। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। यह 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा। देशभर में 10.13 लाख सरकारी स्कूलों में से 5,149 में एक भी छात्र नहीं है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र में जीरो नामांकन वाले इन स्कूलों में से 70% से ज्यादा तेलंगाना व पश्चिम बंगाल में हैं। यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने संसद में दी है। शून्य या 10 से कम छात्रों वाले स्कूलों की संख्या में बीते दो साल में 24% की बढ़ोतरी हुई है।केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को ब्लॉक कर दिया गया है। यह कार्रवाई उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ की गई है, जो कानून द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट प्रसारित कर रहे थे।भाजपा सांसद किरण चौधरी ने रलअठळक बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य लंबे समय से चली आ रही बिखरी हुई व्यवस्था और नीतिगत गतिरोध को समाप्त करना है। यह बिल पुराने बिखरे हुए नियमों को निरस्त कर उनकी जगह लाइसेंसिंग, सुरक्षा एप्रूवल, जवाबदेही और मुआवजे को कवर करने वाला एक फ्रेमवर्क लागू करता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और जन सुरक्षा पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए एक ठोस नींव रखी थी, और अब इस दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार रूप दिया है और आगे बढ़ाया है। वे कहती हैं कि विपक्ष निजीकरण को लेकर बेबुनियाद हंगामा कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि देश की रक्षा कैसे करनी है। जयराम रमेश ने कहा कि विकास को सार्वजनिक क्षेत्र ऑपरेट करे। यदि इसे निजी क्षेत्र ने अपने हाथ में ले लिया तो यह डॉ. होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे हमारे परमाणु कार्यक्रमों का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिकों की दृढ़ मान्यताओं की अनदेखी करने के बराबर होगा।

26 जनवरी से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी

■ सुरक्षाबल अलर्ट, सघन तलाशी अभियान में जुटीं एजेंसियां

एजेंसी

जम्मू। लंबे समय से उधमपुर और किश्तवाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकी 26 जनवरी से पहले किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं। इस इनपुट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर उधमपुर, सांबा और कठुआ जिलों में सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं।लंबे समय से घने जंगलों में सक्रिय आतंकी अब मैदानों की तरफ आ रहे हैं। उधमपुर के मजालता में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबल की सतर्कता और ज्यादा बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार, इन जिलों में आतंकियों के दो से तीन अलग-अलग समूह सक्रिय हैं। इन समूहों में दो-दो या तीनी-तीन लोग शामिल हैं। लंबे समय ये आतंकी घने जंगलों में बनी प्राकृतिक गुफाओं में बनाए ठिकानों में छिपे हुए थे। पहाड़ों में ठंड बढ़ने के साथ ही ये आतंकी अब मैदानी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। इस दौरान बंदूक की नोक पर लोगों से खाना मांगते दिख रहे हैं। मजालता में भी आतंकी ने लोगों से खाने मांगा था। परगवाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर जैश के आतंकी की गिरफ्तारी, उधमपुर के मजालता में मुठभेड़ और सांबा के मानसर में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार लंबे समय से सक्रिय आतंकी पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के लगातार संपर्क में हैं।

सुप्रीम कोर्ट बोला: रिटायरमेंट से पहले ताबड़तोड़ फैसले सुनाना दुर्भाग्यपुर्ण

एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यायपालिका में भ्रष्ट आचरण को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अहम टिप्पणी की गई। कोर्ट ने भ्रष्टाचार का जिक्र किए बिना कहा कि रिटायरमेंट से ठीक पहले जजों का बाहरी कारणों से प्रभावित होकर ताबड़तोड़ फैसला सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा- कुछ जजों में रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले बहुत ज्यादा आदेश पारित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

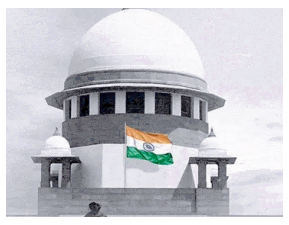

वे आदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे मैच के अंतिम ओवर में छक्के मार रहे हों। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। जज ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत रिटायरमेंट से 10 दिन पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप है कि जज ने कुछ संदिग्ध आदेश पारित किए थे। याचिकाकर्ता जज का रिटायरमेंट 30 नवंबर को होना था। उन्हें 19 नवंबर को दो न्यायिक आदेशों के आधार पर निलंबित किया गया। उनकी ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने कहा कि जज का करियर बेदाग रहा है। सांघी ने दावा किया कि सालाना रिपोर्टों में जज को लगातार हाई रेटिंग मिली है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन आदेशों पर आपत्ति है, उसे हाई कोर्ट में अपील के जरिए सुधारा जा सकता है। इसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है।

सपा नेता आजम खां को कोर्ट से राहत, भड़काऊ भाषण केस में बरी

एजेंसी

रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को फैसला आ गया। कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह मुकदमा भड़काऊ भाषण से संबंधित है जिसे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था। तब आजम खां पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि 29 मार्च 2019 को आजम खां ने

सपा कार्यालय पर भाषण दिया था। इसकी वीडियो प्रसारित की थी। उसमें आजम खां लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़का रहे थे। उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसकी जांच पूरी कर पुलिस ने आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिला

सुल्तान हैथम ने सम्मानित किया, भारत-ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए

एजेंसी

ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, रिन्युएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। इससे पहले पीएम ने बताया कि भारत और ओमान के बीच होने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी उएढअ आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के साझा भविष्य का खाका बताया। मस्कट में भारत-ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की सराहना की। उन्होंने स्टार्टअप से भी अपील की कि वे भारत में निवेश करें, नए प्रयोग करें और भारत-ओमान के साथ मिलकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी सीईपीए

21वीं सदी में हमें नया भरोसा और नई ऊर्जा देगा। यह हमारे साझा भविष्य का खाका है। इससे हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश को नया आत्मविश्वास मिलेगा और हर क्षेत्र में नए अवसरों के दरवाजे खुलेंगे। ओमान पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि कितने भी मौसम बदल जाएं लेकिन भारत से उनकी दोस्ती नहीं बदलेगी। उन्होंने राजधानी मस्कट में भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की तारीफ करते हुए कहा कि वे जहां भी जाते हैं, वहां की विविधता की तारीफ करते हैं। पीएम मोदी बुधवार शाम को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने औपचारिक बातचीत भी की। रात में सईद ने पीएम मोदी के लिए डिनर भी रखा। सुल्तान हैथम ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। यह ओमान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ओमान को अरब जगत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और इसके पीछे है सुल्तान हैथम की कूटनीति। अमेरिका-ईरान, इजराइल-हमास संघर्ष में भी सुल्तान हैथम पर्दे के पीछे समाधान की राह बनाते रहे हैं। यमन संकट में भी ओमान एकमात्र खाड़ी देश है जो तटस्थ रहा और 25 हजार से अधिक यमनी शरणार्थियों को शरण दी। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच भी 2023 में मस्कट में डील ब्रेक कराई थी। सुल्तान हैथम को विंटेज कारों का भी शौक है। उनके गैरेज में 130 साल पुरानी भाप से चलने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ फेरारी और रोल्स रॉयस भी मौजूद हैं। इसके अलावा मर्सिडीज-मेबैक और बेंटले जैसी दुनिया की सबसे महंगी और चुनिंदा कारें भी शामिल हैं। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक (70) दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपरयॉट (164 मीटर) के मालिक हैं। यॉट फलक अल सलामह की कीमत 4500 करोड़ रु. है।

दिल्ली में सख्ती: जगह-जगह गाड़ियों की चेकिंग

सिर्फ बीएस-6 इंजन गाड़ियों को एंट्री, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जा रहा

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार-गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए है। दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इससे कम मानक वाले, दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जा रहा है। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने-जाने वाली 12 लाख गाडियों पर असर पड़ा है। नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, गुरुग्राम से 2

लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया है। दिल्ली में 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम भी लागू हो गया है। पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (ढवउ) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह-जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए पेट्रोल पंप से लौटाया जा रहा है। वहीं, नॉन इर-6 इंजन वाली गाड़ियां बॉर्डर से यू-टर्न ले रही हैं। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 कॉमर्शियल और निजी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है।

नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का चालान किया जा रहा है या वाहन को यू-टर्न करवाया जा रहा है। जिन वाहनों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, उन पर 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है। दिल्ली में GRAP-4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बैन है। CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुमार्ना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्रांति की नींव रखने वाले काकोरी के शूरवीरों को नमन

बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारत का राजनीतिक परिदृश्य तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने देश में जन-जागरण की लहर पैदा की थी। 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था लेकिन फरवरी 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने से देश के एक बड़े वर्ग, विशेषकर युवा क्रांतिकारियों में गहरी निराशा फैल गई।

(लेखक- - योगेश कुमार गोयल)

- काकोरी कांड- आजादी के संघर्ष का अमर अध्याय

(काकोरी शहीद दिवस (19 दिसम्बर) पर विशेष)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल राजनीतिक आंदोलनों, प्रस्तावों और समझौतों का क्रम नहीं है बल्कि यह उन असंख्य क्रांतिकारियों की त्यागमयी गाथा भी है, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन बलिदानों ने गुलामी की जड़ों को भीतर से हिलाया और जनता के मन में यह विश्वास जगाया कि अंग्रेजी हुकूमत अजेय नहीं है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक और निर्णायक घटना है काकोरी कांड, जिसने न केवल ब्रिटिश सत्ता को गहरी चुनौती दी बल्कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का वह अध्याय है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि आजादी केवल याचिकाओं और प्रार्थनाओं से नहीं मिलेगी बल्कि उसके लिए साहस, संगठन और बलिदान की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों को केवल इतिहास के पात्र नहीं बल्कि क्रांति की नींव रखने वाले शूरवीर माना जाता है। उनकी शहादत की स्मृति में हर वर्ष 19 दिसम्बर को काकोरी शहीद दिवस मनाया जाता है, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी का बोध कराता है।

बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारत का राजनीतिक परिदृश्य तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने देश में जन-जागरण की लहर पैदा की थी। 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था लेकिन फरवरी 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने से देश के एक बड़े वर्ग, विशेषकर युवा क्रांतिकारियों में गहरी निराशा फैल गई। वे मानते थे कि जब अंग्रेज दमन और हिंसा का सहारा ले रहे हैं, तब केवल अहिंसा के माध्यम से आजादी पाना कठिन है। यही वह ऐतिहासिक मोड़ था, जहां से संगठित क्रांतिकारी आंदोलन ने नई दिशा पकड़ी। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी युवाओं ने यह ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। इसी सोच के परिणामस्वरूप 1923 में शचीन्द्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं बल्कि एक ऐसे स्वतंत्र, गणराज्यात्मक भारत की स्थापना करना था, जहां शोषण और अन्याय का कोई स्थान न हो।

एचआरए के प्रमुख सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेशचंद्र चटर्जी, शचीन्द्रनाथ बख्शी जैसे साहसी क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे तेजस्वी क्रांतिकारी भी इस विचारधारा से जुड़े। संगठन का स्पष्ट मत था कि क्रांति के लिए संसाधन चाहिए और संसाधनों के लिए धन। लेकिन चंदा मांगना न केवल संगठन की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता था बल्कि अंग्रेजी खुफिया तंत्र को भी सतर्क कर सकता था। ऐसे में निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के ही खजाने को निशाना बनाया जाए। इस विचार को कार्यरूप देने की जिम्मेदारी संगठन के सेनापति पं. राम प्रसाद बिस्मिल को सौंपी गई। प्रारंभिक प्रयासों में क्रांतिकारियों ने कुछ धन जुटाने की कोशिश की, लेकिन वह हथियारों और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि सीधे सरकारी खजाने पर हाथ डाला जाए। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि अत्यंत जोखिम भरा भी, क्योंकि असफलता की स्थिति में इसका परिणाम मृत्यु या आजीवन कारावास हो सकता था।

8 अगस्त 1925 को बिस्मिल के घर एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की विस्तृत योजना बनाई गई। अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को एचआरए के दस क्रांतिकारी सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्रनाथ बख्शी, मन्मथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुकुंदी लाल शामिल थे। लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोका गया। योजना के अनुसार, राजेंद्र लाहिड़ी ने नेतृत्व संभाला और कुछ ही क्षणों में सरकारी खजाने को कब्जे में ले लिया गया। यह कार्रवाई इतनी सुनियोजित थी कि यात्रियों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि दुर्भाग्यवश एक आकस्मिक गोली चलने से एक यात्री की मृत्यु हो गई, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने पूरे मामले को और अधिक संगीन बनाने के लिए प्रमुख आधार बनाया।

इस लूट में कुल 4601 रुपये प्राप्त हुए, जो उस समय एक बड़ी राशि थी। अगले ही दिन यह खबर अखबारों के माध्यम से पूरे देश और विदेश में फैल गई। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक में इस घटना की चर्चा हुई। ब्रिटिश सरकार हिल गई और उसने इसे अपनी सत्ता के लिए खुली चुनौती माना। इसके बाद जो दमनचक्र चला, वह भारतीय इतिहास के सबसे कठोर अभियानों में से एक था। ब्रिटिश सरकार ने एचआरए के लगभग 40 क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। लंबी सुनवाई और कठोर पूछताछ के बाद अंग्रेजी अदालत ने चार क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 17 दिसम्बर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। इसके दो दिन बाद 19 दिसम्बर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी गई। इन फांसियों ने पूरे देश को झकझोर दिया। हिंदू-मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल बने बिस्मिल और अशफाक की मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का संघर्ष था। उनकी शहादत ने असहयोग आंदोलन के बाद ठहर गई क्रांतिकारी चेतना को फिर से प्रज्वलित कर दिया।

काकोरी कांड का सबसे अनछुआ पहलू यह है कि यह केवल धन लूट की घटना नहीं थी बल्कि यह एक वैचारिक विद्रोह था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की नैतिक वैधता को चुनौती देना और यह संदेश देना था कि भारत अब दासता स्वीकार नहीं करेगा। इस घटना ने आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को भी गहराई से प्रभावित किया। आज, जब हम काकोरी शहीद दिवस मनाते हैं तो यह केवल अतीत को स्मरण करने का अवसर नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा लेने का दिन है। काकोरी के शूरवीरों ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्त्तव्य भी है उसकी रक्षा का, उसकी गरिमा बनाए रखने का। काकोरी कांड के शहीदों का बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाता रहेगा कि भारत की आजादी यूं ही नहीं मिली बल्कि इसके पीछे अनगिनत वीरों का लहू बहा है। भारत आज भी उनका ऋणी है और सदैव रहेगा।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संपादकीय

मौत की धुंध

उस घटना की कल्पना करके भी रूह कांप जाती है, जिसमें मथुरा के निकट, मंगलवार तड़के घने कोहरे के चलते कई वाहनों के आपस में टकराने से तेरह लोग जिंदा जल गए। घने अंधेरे में बड़ी संख्या में लोग आग में झुलसे और घायल हुए। मरने वाले निर्दोष लोग अपने-अपने जरूरी कामों के लिए जल्दी पहुंचने की चाहत में रात के सफर पर निकले थे। लेकिन हालात उन्हें मौत के मुंह में ले गये। मंगलवार को अमंगल का यह सिलसिला पंजाब तक चला, जहां सुबह घने कोहरे के चलते पांच लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। बरनाला व तपामंडी में हुए दो सड़क हादसों में एक ही परिवार के तीन लोगों समेत पांच लोगों की मौत हुई। वजह वही, घने कोहरे के चलते दृश्यता में कमी और स्थिति का आकलन न कर पाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। वहीं तपामंडी के व्यापारी की पत्नी व बेटी की मौत रास्ते में खड़े ट्रक से उनकी कार के टकराने से हुई। इससे पहले रविवार सुबह कोहरे के कोहराम से 66 वाहनों के टकराने से एक छात्रा समेत चार लोगों की मौत हरियाणा में भी हुई। चरखी दादरी में एक स्कूल बस व रोडवेज की बस की आमने-सामने की टक्कर में एक ग्यारहवीं की छात्रा की मौत हो गई और तीस से अधिक छात्राएं व शिक्षक, बस चालक समेत घायल हो गए। वहीं तेज रफ्तार वाले नेशनल हाईवे 152-डी पर एक के बाद एक, अनेक वाहन दृश्यता की कमी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई और 24 से अधिक लोग घायल हो गए। निश्चय ही निर्दोष लोगों का यूं असमय काल-कवलित होना बेहद दुखद ही है। आखिर हर साल जाड़े के दिनों में धुंध या कोहरे की वजह से होने वाले हादसों के लिए हम क्यों अभिशप्त हैं? आखिर इन दुर्घटनाओं को टालने की गंभीर कोशिश सरकार, समाज व वाहन चालकों की तरफ से क्यों नहीं की जाती? विडंबना है कि जब हमने चांद व मंगल ग्रह तक दस्तक दे दी है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों के जानमाल की रक्षा के लिए धुंध से मुक्ति की तकनीक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? निश्चय ही प्रकृति की लीला का मुकाबला कर पाना संभव नहीं, लेकिन कमोबेश दुर्घटनाओं की संख्या कम करके जान-माल का नुकसान कम करने का प्रयास तो करें। यह सजगता नागरिकों के स्तर पर भी जरूरी है। यात्रा के समय के चयन और धुंध के बीच वाहन चालन में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर पर्याप्त रोशनी और धुंध में दृश्यता बढ़ाने के तकनीकी प्रयास किए जाएं। मौसमी बाधा के बीच दुर्घटना का एक बड़ा कारण राजमार्गों के किनारे अवैध रूप से जगह-जगह खोले गए ढाबे भी बनते हैं। दरअसल, होटल-ढाबों के पास वाहनों को अपने परिसर में खड़ा करने की जगह नहीं होती, जिसके चलते ट्रक व अन्य वाहन सड़कों में खड़े रहते हैं। जिसके चलते अक्सर तेजी से आने वाले वाहन दृश्यता की कमी से इन खड़े वाहनों से टकराकर दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं। पिछले माह राजस्थान के फलोदी के निकट एक टेम्पो ट्रेवलर के सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से टकराने से दस महिलाओं व चार बच्चों समेत पंद्रह लोगों की मौत हुई थी। इस घटना पर स्वत- संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने लगातार हादसों की वजह बन रहे इन अवैध होटलों-ढाबों पर नियंत्रण हेतु पूरे देश के लिये दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत बतायी। कई अध्ययनों में हादसों की वजह सड़कों के डिजाइन में कमी को भी बताया गया। सवाल है कि जब देश में अच्छी-तेज सड़कों का जाल तीव्र गति से बिछाया जा रहा है तो सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना भी तो नीति-नियंताओं की जवाबदेही बनती है? हादसों के लिए सिर्फ चालकों को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता।

अफ्रीका की धरती पर भारत का आत्मीय स्वागत, इथियोपिया में मोदी युग की नई साझेदारी

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

अफ्रीका के हृदय कहे जाने वाले इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा केवल एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत-इथियोपिया के हजारों वर्ष पुराने संबंधों को नई ऊर्जा देने वाला ऐतिहासिक क्षण बन गया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अदीस अबाबा के बोले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, वहां आत्मीयता, सम्मान और अपनत्व का ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को स्पष्ट कर दिया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली स्वयं प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे और सबसे विशेष बात यह रही कि वे खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट से होटल तक लेकर गए। यह दृश्य केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि अफ्रीकी संस्कृति में मित्रता और भरोसे का प्रतीक माना जाता है।

एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इथियोपिया की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली पारंपरिक कॉफी सेरेमनी के माध्यम से उनका अभिनंदन हुआ। यह रस्म इथियोपिया में सम्मान और अपनत्व का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। प्रवासी भारतीयों ने 'भारत माता की जय' और 'मोदी-मोदी' के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों, पारंपरिक नृत्यों और भारतीय तिरंगे के बीच पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस गर्मजोशी को महसूस करते हुए कहा कि इथियोपिया की धरती पर आकर उन्हें अपनेपन का अहसास हो रहा है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इथियोपिया की ओर से किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सर्वोच्च अलंकरण है। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का गौरव बताया और कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया की साझा मित्रता, साझा मूल्यों और साझा भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अफ्रीका के साथ साझेदारी को अपने शर्तों पर नहीं, बल्कि अफ्रीका की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़ाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि सभ्यतागत साथी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत औपनिवेशिक शासन से जूझ रहा था, तब इथियोपिया भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। दोनों देशों ने कभी एक-दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाए और हमेशा शांति, संप्रभुता और समानता के सिद्धांतों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत-इथियोपिया संबंध अब केवल सहयोग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें रणनीतिक साझेदारी में बदला जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर भी दोनों नेताओं के विचार एक जैसे दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसके समर्थन या औचित्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इथियोपिया की ओर से आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद भी दिया। व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और इथियोपिया के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इथियोपिया में भारत सबसे बड़ा निवेशक है और भारत, इथियोपिया के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत से इथियोपिया को होने वाला निर्यात लगभग 4433 करोड़ रुपये का है, जबकि इथियोपिया से भारत का आयात करीब 442 करोड़ रुपये का है। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है। भारत इथियोपिया को मुख्य रूप से लोहा और स्टील, दवाइयां और फार्मास्युटिकल उत्पाद, मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और इंजीनियरिंग सामान का निर्यात करता है। भारतीय फार्मा कंपनियां इथियोपिया के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और वहां सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही हैं। वहीं इथियोपिया से भारत दालें, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, तिलहन बीज, चमड़ा और मसालों का आयात करता है। इथियोपिया का कॉफी उद्योग भी विश्व प्रसिद्ध है और भारत के लिए इसमें सहयोग की नई संभावनाएं हैं।

भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत और इथियोपिया के बीच की दूरी लगभग साढ़े चार से पांच हजार किलोमीटर के आसपास है। नई दिल्ली से अदीस अबाबा की हवाई दूरी करीब 4500 किलोमीटर मानी जाती है। इतनी दूरी के बावजूद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक निकटता इस यात्रा में साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दूरी कभी भी दिलों के बीच की नजदीकी को कम नहीं कर सकती, अगर सोच और लक्ष्य एक जैसे हों।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित किया कि भारत और इथियोपिया दोनों ही ग्लोबल साउथ के प्रमुख साझेदार हैं। विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने में दोनों देशों की भूमिका अहम है। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक असमानता जैसे मुद्दों पर भारत और इथियोपिया के विचार मिलते-जुलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की आर्थिक प्रगति और अफ्रीका में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना की। इस पूरे दौरे के दौरान जो बात सबसे अधिक उभरकर सामने आई, वह थी आपसी विश्वास और सम्मान। एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत से लेकर सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने तक, हर क्षण यह संदेश देता रहा कि भारत और इथियोपिया के रिश्ते केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दिल से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा आने वाले वर्षों में भारत-इथियोपिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की नींव रखती है। अंततः कहा जा सकता है कि इथियोपिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत और उन्हें मिला सर्वोच्च सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह यात्रा अफ्रीका के साथ भारत की गहरी होती साझेदारी, ग्लोबल साउथ की मजबूत होती आवाज और एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है, जहां सहयोग, सम्मान और साझा विकास ही संबंधों की बुनियाद होंगे।

(रु 103 जलवन्त टाऊनशिप पूणा बॉम्बे मार्केट रोड, नियर नन्दालय हवेली सूरत मो 99749 40324 वरिष्ठ पत्रकार,साहित्यकार, स्तम्भकार)

चिंतन मनन

नदी और सागर

सुखदेव ऋषि के आश्रम में कई शिष्य रहते थे। उनमें अनुज नामक शिष्य काफी तेज था। धीरे-धीरे वह स्वयं को अन्य शिष्यों से श्रेष्ठ मानकर दूसरों को हीन समझने लगा। ऋषि उसके अंदर छिपे अहं को समझ गए और उसे एक दिन अपने साथ एक सागर के पास ले गए। विशालकाय सागर अत्यंत आकर्षक दिख रहा था। उसकी लहरें जब अठखेलियां करतीं तो मन प्रसन्न हो जाता। ऋषि ने अनुज से सागर का पानी पीने के लिए कहा। अनुज ने जैसे ही पानी मुंह में डाला, वैसे ही उसने बुरा सा मुंह बनाकर पानी बाहर निकाल दिया और बोला, गुरुजी, यह पानी तो खारा है। मेरा मुंह का स्वाद कसैला हो गया।

ऋषि उसकी बात सुनकर मुस्कराए। वह उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। आगे एक छोटी सी नदी आई। नदी का जल शांत था। ऋषि ने अनुज से नदी का जल पीने के लिए कहा। अनुज ने जैसे ही जल मुंह में डाला, वैसे ही उसके मन को अत्यंत तृप्ति मिली। वह बोला, गुरुजी, नदी के जल ने मुंह का स्वाद बढ़ा दिया है। इतना ठंडा और मीठा जल बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि इतने बड़े सागर का पानी एकदम खारा था।

उसके ऐसा ही कहते ही ऋषि बोले, पुत्र, देखा तुमने, छोटे-बडे से कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने व्यवहार और सद्कार्यो से अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। तुमने सागर के अहं को देखा। वह सब कुछ अपने में ही भरे रहता है। लेकिन इसका जल खारा होता है। जबकि छोटी सी नदी जो पाती है उसका अधिकांश बांटती है, इसलिए उसके जल में मिठास है।

व्यक्ति को बड़े होने पर भी अहं को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए अन्यथा उसका हाल भी सागर की तरह ही होता है।

मेरे विचार में तुम मेरी बातों का अर्थ अच्छी तरह समझ गए हो। अनुज को अपनी गलती का अहसास हो गया। उसने अपने भीतर से अपना अहं निकाल फेंका।

विचार मंथन

वीबी- जी राम जी का 125 दिन वाला झुनझुना

(लेखक- सनत जैन)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को ग्रामीण भारत के लिए जीवनरेखा माना गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य था, हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार और समय पर मजदूरी मिले। जमीनी हकीकत पिछले वर्षों में इससे बिल्कुल उलट दिखाई देती है। आज स्थिति यह है, 100 दिन की कानूनी गारंटी होने के बावजूद मजदूरों को औसतन 40 से 50 दिन का औसत से अधिक काम नहीं मिल पा रहा है। जो काम मिलता भी है, उसकी मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में देरी अब अपवाद नहीं, बल्कि एक व्यवस्था बन चुकी है। कई राज्यों में मजदूरों को कई महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खपत घटती है, कर्ज बढ़ता है, और पलायन बढ़ता है। गांवों में रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन शहरों में भी अब मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस विफलता की जिम्मेदारी तय करने एवं व्यवस्था में सुधार करने के बजाय सरकार की ओर से विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी बिल में 125 दिनों के रोजगार देने का जो वायदा किया जा रहा है उसे विपक्षी दल, सरकार का 125 दिन का झुनझुना कह रहे हैं। नए प्रस्ताव में एक ओर रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों पर 40 प्रतिशत हिस्सेदारी का बोझ डाल दिया गया है। पहले से ही कर्ज में डूबी राज्य सरकारों के लिए यह अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी निभाना लगभग असंभव है। नतीजे में राज्यों को या तो मजदूरों की संख्या को कम करना होगा, या भुगतान में देरी होगी। इस योजना के तहत अव्यवस्था फैलेगी। इस तरह 125 दिन का दावा कागजों तक सीमित रह जायेगा। मजदूरों के अधिकार फाइलों तक सीमित रह जाएंगे। सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है, कि इस नए बिल में केंद्र सरकार को यह अधिकार देने की बात की जा रही है, कि कहां मजदूरी देनी है, कहां नहीं। इसका फैसला दिल्ली के मंत्रालय में होगा। इससे मनरेगा की आत्मा गारंटीड अधिकार का वजूद ही खतरे में पड़ जायेगा। मजदूरी के निर्णय का अधिकार पंचायत और राज्य सरकार से निकलकर केंद्र सरकार के विवेकाधिकार में आ जाएगा और राजनीतिक टूल्स बनकर रह जाएगा। पश्चिम बंगाल में पिछले 4 साल से मनरेगा के मजदूरों को काम नहीं मिला है। जो काम मजदूरों ने किया था, उसका भुगतान भी नहीं हुआ है। अभी जब यह हाल हैं, तो आगे क्या होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। यह योजना मजदूरों के कल्याण की कम और राजनीति का हथियार ज्यादा बनकर रह जाएगी। योजना के विरोध करने वालों का कहना है, कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर योजना करने के राजनीतिक फायदे जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल सिद्धांतों को कमजोर कर दिया गया है। 125 दिन का शोर मचाकर मनरेगा को अप्रासंगिक बनाने और योजना को बंद करने का अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 100 दिन की मौजूदा गारंटी ही पूरी नहीं हो पा रही, तो 125 दिन के वादे को किस आधार पर भरोसेमंद माना जा सकता है? वह भी तब जब राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर भारी कर्ज हो। तब बिल में जो सपने दिखाए जा रहे हैं, उन सपनों पर अब विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है, कि मौजूदा कानून को ईमानदारी से लागू किया जाए। मजदूरों के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। समय पर सभी पंजीकृत मजदूरों को 100 दिन की अनिवार्य रूप से मजदूरी दी जाए। मजदूरी का भुगतान निश्चित समय सीमा पर हो। इसके लिए पर्याप्त बजट केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के जारी किया जाए। लोकसभा में बिल पेश किया गया, उस पर बहस हुई और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच गुरुवार 18 दिसंबर को इसे मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक पर बुधवार को आधी रात के बाद चर्चा समाप्त हुई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें सदन के समक्ष रखे। महात्मा गांधी का नाम हटाकर जिस तरह से विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी- जी राम जी के नाम पर योजना में बदलाव किया जा रहा है, उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा अपने-अपने तर्क रखे हैं।

बहरहाल लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को मंजूरी दे दी गई। विधेयक पारित होने के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। महात्मा गांधी का सपना था कि भारत गांवों का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एक्मे सोलर ने 4,725 करोड़ का वित्तपोषण किया हासिल

वित्तपोषण से कंपनी को नई परियोजनाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थानों से कुल 4,725 करोड़ रुपये का ऋण हासिल किया। इस वित्तपोषण का लक्ष्य परियोजनाओं की पूंजी संरचना को अनुकूलित करना और वित्तपोषण लागत को कम करना है। नई परियोजनाओं के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2,716 करोड़ रुपये और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने 800 करोड़ रुपये प्रदान किए। मौजूदा 300 मेगावाट एक्मे सीकर सोलर परियोजना के लिए यस बैंक ने 1,209 करोड़ रुपये का पुनर्वित्तपोषण किया। इससे ऋण लागत में प्रारंभिक 1.70 प्रतिशत और अंततः 1.95 प्रतिशत की कमी संभव हुई। यह यस बैंक द्वारा एक्मे सोलर के लिए पहला दीर्घकालिक पुनर्वित्तपोषण है। इस वित्तपोषण से कंपनी को नई परियोजनाओं का विस्तार करने और पूंजी संरचना मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही वित्तीय लागत कम होगी, जो एक्मे सोलर के लिए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर जनवरी से वाहनों की कीमत बढ़ाएगी

नई दिल्ली । कच्चे माल की लागत और व्यापक आर्थिक कारणों के चलते कंपनी ने जनवरी 2026 से अपने वाहनों की कीमतों में 2 फीसदी तक बढ़ोतरी की घोषणा की। बढ़ोतरी सभी मॉडलों और संस्करणों पर समान नहीं होगी; प्रत्येक वाहन के लिए अलग रेट तय होगा। मर्सिडीज-बेंज इंडिया और बीएमडब्ल्यू ने भी जनवरी से कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है।

सीएनजी-पीएनजी की कीमत में राहत, 2026 से नई टैरिफ नीति लागू

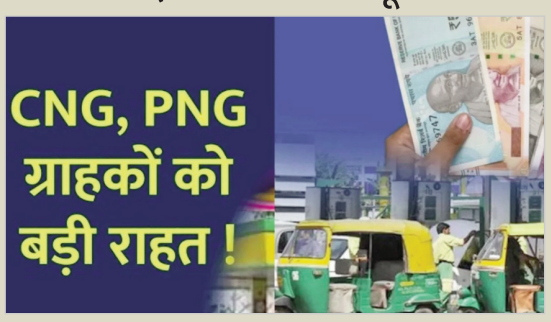

- उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2-3 रुपए की बचत होगी

नई दिल्ली । देशभर में सीएनजी और घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने नई टैरिफ रैशनलाइजेशन नीति लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत होगी। पीएनजीआरबी के एक सदस्य के अनुसार यह बदलाव ट्रांसपोर्ट और घरेलू उपयोग दोनों में लाभ पहुंचाएगा। पुरानी प्रणाली में दूरी के आधार पर तीन जोन थे- 200 किलोमीटर तक 42 रुपये, 300-1,200 किलोमीटर 80 रुपये और 1,200 किलोमीटर से अधिक 107 रुपये। नई प्रणाली में इसे घटाकर दो जोन किया गया है। जोन-1 के लिए अब 54 रुपये प्रति यूनिट तय किए गए हैं, जिससे शहरों के उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ होगा नई टैरिफ नीति 312 क्षेत्रों और 40 सीजीडी कंपनियों पर लागू होगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सीएनजी और घरों में पीएनजी इस्तेमाल करने वाले परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। पीएनजीआरबी निगरानी सुनिश्चित करेगा कि कम दर का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचे। यह पहल प्राकृतिक गैस के व्यापक और सब्सिडाइज्ड उपयोग को बढ़ावा देगी।

2026 में नई हुंडई वरना ज्यादा मॉडर्न लुक के साथ हो सकती है लॉन्च

नई दिल्ली ।

नई हुंडई वरना को कंपनी और ज्यादा आकर्षक बनाने की तैयारी में है। कंपनी द्वारा नए साल 2026 में वरना का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में विदेश में इसका टेस्ट म्यूल देखा गया है, जिससे इसके संभावित बदलावों को लेकर संकेत मिले हैं।

टेस्टिंग के दौरान कार पूरी तरह कैमोफ्लाज में थी, लेकिन फ्रंट और रियर हिस्से को खासतौर पर ढका गया था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन्हीं हिस्सों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नई वरना में री-डिजाइन्ड ग्रिल, नया बंपर और ज्यादा शार्प फ्रंट प्रोफाइल मिलने की उम्मीद है, जिससे कार को प्रीमियम और स्पोर्टी लुक मिलेगा। कार का ओवरऑल सिलुएट मौजूदा मॉडल जैसा ही रखा जाएगा, ताकि इसकी पहचान बनी रहे।

हालांकि, नए अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ अपडेटेड बंपर व टेललैंप डिजाइन से लुक में फ्रेशनेस जोड़ी जा सकती है। केबिन में बड़े बदलाव की बजाय फीचर्स और फिनिश पर फोकस किया जा सकता है। डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप जारी रहने की संभावना है, लेकिन नए कम्फर्ट और सेफ्टी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। पावरट्रेन के मामले में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है और मौजूदा इंजन ऑप्शन्स ही जारी रह सकते हैं।

रुपया तेजी के साथ बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गुरुवार को 10 पैसे की तेजी के साथ ही 90.27 पर बंद हुआ। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.35 पर खुला। कारोबार के दौरान इसमें हल्की मजबूती देखी गई और यह 90.32 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि शुरुआती सत्र में रुपये में कमजोरी भी दर्ज की गई और यह 90.38 के स्तर तक फिसल गया। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 फीसदी की बढ़त के साथ 98.41 पर रहा, जिससे उभरती मुद्राओं पर दबाव बना रहा।

पेटीएम को आरबीआई से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला

- ऑनलाइन भुगतान की पहले मिल चुकी थी अनुमति

नई दिल्ली । वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऑफलाइन भुगतान और सीमा-पार लेनदेन के लिए पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में संचालन की अनुमति प्राप्त हुई है। इससे पहले, 26 नवंबर 2025 को पीपीएलएल को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी दी गई थी। आरबीआई की अनुमति के बाद अब पेटीएम ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीमा-पार सभी प्रकार के भुगतान लेनदेन संभाल सकता है। यह अनुमति भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत दी गई है। इस नए लाइसेंस से पेटीएम को अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को आसान और तेज़ बनाने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे कंपनी का कारोबार क्षेत्र और ग्राहकों तक पहुँच दोनों बढ़ेंगे।

शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर सकंतों के साथ ही बिकवाली के दबाव के कारण आई। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 84,481.81 पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई 25,815.55 पर बंद हुआ। आज दिन भर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहा, जिससे निवेशक सतर्क दिखे और आई शेयरों में कुछ खरीदारी हुई। इससे भी बाजार पर दबाव पड़ा। इससे पहले आज सुबह

एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ खुले। वैश्विक बाजारों में जारी दबाव का असर घरेलू शेयर बाजारों पर देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत से ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में कमजोरी बनी रही, जिससे निवेशकों की धारणा सतर्क नजर आई। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 84,518 अंक पर खुला। हालांकि, खुलते ही इसमें बिकवाली बढ़ गई। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 160.74 अंक की गिरावट के साथ 84,398.91 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी कमजोरी के साथ 25,764 अंक पर खुला। सुबह की शुरुआत के बाद 53.85 अंक गिरकर 25,789 अंक पर ट्रेड करता दिखा। बाजार के जानकारों ने कहा` कि अमेरिकी बाजारों में आई तेज गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिली, जिसका असर घरेलू शेयर बाजारों पर पड़ा। उन्होंने बताया कि तकनीकी रूप से निफ्टी का निकट-कालिक रुझान कमजोर बना हुआ है और यह अपने ऑल टाइम हाई स्तर 26,326 से नीचे ही घूम रहा है। हर छोटी तेजी पर बिकवाली हावी हो रही है, जिससे बाजार में बियर्स की पकड़ बनी हुई है। उनके अनुसार निफ्टी के लिए 25,693 का स्तर अहम सपोर्ट है। यदि निफ्टी इस स्तर के नीचे फिसलता है तो गिरावट और तेज हो सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि पिछली ट्रेडिंग में एफआईआई ने नेट खरीदारी की थी और आरबीआई के समर्थन से रुपये में मजबूती आई है। इसके बावजूद मौजूदा हालात को देखते हुए निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

ऐ शियाई बाजार में` गिरावट- वैश्विक बाजारों में एशियाई शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे। इसकी वजह यह रही कि वॉल स्ट्रीट के निवेशक लगातार टेक्नोलॉजी शेयरों से दूरी बना रहे हैं और उनका ध्यान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगामी संबोधन पर टिका हुआ है। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.53 फीसदी गिरा, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.36 फीसदी नीचे आया, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी, एएसएक्स 200 0.3 फीसदी की हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ।

अमे रिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद- अमेरिका में भी वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। एसएंडपी 500 में 1.16 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि नैस्डैक कंपोज़िट सबसे ज्यादा टूटा और इसमें 1.81 फीसदी की गिरावट आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कारोबार को लेकर बनी चिंताओं के चलते टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव बना रहा। वहीं, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 0.47 फीसदी फिसल गया।

भारत का होम लोन बाजार.....2035 तक 150 लाख करोड़ तक पहुंच सकता

मुंबई।

भारत के होम लोन मार्केट में तेजी से बदलाव दिख रहा है। अगले एक दशक यानी 2035 तक होम लोन का वितरण 150 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसकी जानकारी गुरुवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

एक रिपोर्ट के अनुसार, जनसांख्यिकी, शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और नीतिगत समर्थन जैसे शक्तिशाली कारक मिलकर भारत के वित्तीय सेवा परिदृश्य में सबसे स्थायी संरचनात्मक ऋण मौकों में से एक की नींव रख रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात का ज़िक्र किया गया हैं कि भारतीय बाजारों में चीजों को गिरवी रखकर लोन लेने की पहुंच मात्र जीडीपी के 11 प्रतिशत पर है, जो कि ग्लोबल बेंचमार्क से काफी कम हैं। इसके बाद भी भारत के लोन बाजारों में काफी सारे मौके मौजूद हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, 2035 तक देश की शहरी आबादी 65 करोड़ से अधिक होगी और शहरीकरण की दर 43 प्रतिशत तक बढ़ेगी। इसकी वजह राजमार्गों, मेट्रो रेल नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और तेजी से उभरते सैटेलाइट टाउनशिप में निवेश होना है। इसके अलावा, सरकारी पहलें अफोर्डेबिलिटी को मजबूत कर रही हैं और सप्लाई बनाने में मदद कर रही हैं, जिसमें पीएमएवाई 2.0 का मकसद 30 मिलियन अतिरिक्त घरों के लिए फाइनेंसिंग को सपोर्ट करना है, एसडब्ल्यूएएमआईएच-2 का लक्ष्य 100,000 अटकी हुई मिड-इनकम हाउसिंग यूनिट्स को पूरा करना है, और 1 लाख करोड़ रुपए का

अर्बन चैलेंज फंड भारतीय शहरों को भविष्य के ग्रोथ हब में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, रेरा को लगातार लागू करने से रियल एस्टेट इकोसिस्टम में पारदर्शिता और खरीदारों का भरोसा भी बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत बैलेंस शीट, बढ़ती अफोर्डेबिलिटी और कई सालों तक डिमांड दिखने की वजह से हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री भारत की आर्थिक ग्रोथ के अगले दौर का एक अहम हिस्सा बनने के लिए तैयार है।

गूगल पे और ए क्सिस बैंक ने पेश किया यूपीआई संचालित क्रेडिट कार्ड

नई दिल्ली । गूगल पे और ऐ क्सिस बैंक ने मिलकर गूगल पे फ्लेक्स ऐ क्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए है, जो यूपीआई भुगतान की सरलता के साथ क्रेडिट कार्ड की सुविधा एक ही मंच पर चाहते हैं। यह कार्ड पूरी तरह गूगल पे अनुप्रयोग में एकीकृत है, जिससे उपयोगकर्ताओं को भौतिक कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी। उपयोगकर्ता किसी भी दुकान पर लगे यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके क्रेडिट पर भुगतान कर सकते हैं। रूपे नेटवर्क पर आधारित होने के कारण यह कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह स्वीकार किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और आसान बनाना और उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड का अनुभव सरलता से प्रदान करना है।

अमेरिका में जेनेरिक दवाओं पर विदेशी निर्भरता, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चिंता

- चीन में बनते हैं एंटीबायोटिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले 90 प्रतिशत एपीआई

वाशिंगटन।

अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं और उनके एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आता है। सीनेटर रिक स्कॉट ने चेतावनी दी है कि यह स्थिति अमेरिकी परिवारों के लिए स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा है। 2002 में अमेरिका अपनी जरूरत की 83 प्रतिशत दवाएं खुद बनाता था, जो 2024 में घटकर केवल 37 प्रतिशत रह गई हैं। एंटीबायोटिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले लगभग 90 प्रतिशत एपीआई चीन में बनते हैं। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली शीर्ष 100 जेनेरिक दवाओं में से 83 प्रतिशत के एपीआई का कोई भी स्रोत अमेरिका में नहीं है। भारत से अमेरिका में लगभग 50 प्रतिशत जेनेरिक दवाएं आती हैं, लेकिन भारत खुद अपने 80 प्रतिशत एपीआई के लिए चीन पर निर्भर है। विदेशी फैक्ट्रियों में अक्सर निरीक्षण कम होता है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक हैं। इनमें स्थायी विकलांगता और मौत जैसे गंभीर परिणाम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि चीन कभी भी दवाओं की आपूर्ति रोक सकता है, जिससे बुजुर्ग, सेना के जवान और आम

नागरिक प्रभावित होंगे। अमेरिकी एफडीए घरेलू फैक्ट्रियों की तुलना में विदेशों में कड़े निरीक्षण नहीं कर पाता और कई बार नियमों के उल्लंघन को छूट भी दे देता है। सीनेटर रिक स्कॉट और सीनेटर किर्स्टन गिलिब्रैंड ने ड्रग सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर करने के लिए जांच और सुनवाई शुरू की हैं। उनका उद्देश्य अमेरिकी परिवारों को यह जानने का अधिकार देना है कि उनकी दवाओं में कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं।

नई देसी कैब सेवा जनवरी से दिल्ली में होगी शुरू

- 30 रुपए में 4 किमी सफर, ओला-उबर की बढ़ी टेंशन!

नई दिल्ली ।

नई देसी कैब सेवा भारत टैक्सी जल्द ही दिल्ली में शुरू होने जा रही है। फिलहाल इसका ट्रायल दिल्ली और गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में चल रहा है। यह सेवा जनवरी में औपचारिक रूप से लॉन्च की जाएगी। भारत टैक्सी का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड कर रही है। यह पूरी तरह ड्राइवर-स्वामित्व वाला मॉडल है, यानी ड्राइवर ही कंपनी के मालिक हैं। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइवर-मालिकाना टैक्सी सेवा है। अब तक 1 लाख से अधिक ड्राइवर प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिनमें कार, ऑटो-रिक्शा और बाइक टैक्सी चालक शामिल हैं। शुरुआत में ड्राइवर को 100 फीसदी किराया मिलेगा। भविष्य में 20 फीसदी शुल्क लागू हो सकता है, लेकिन यह राशि ड्राइवरों को इंसेंटिव के रूप में वापस दी जाएगी। इस मॉडल का उद्देश्य ड्राइवरों को अधिक लाभ और पारदर्शिता देना है।

भारत टैक्सी का किराया अन्य कैब सेवाओं से सस्ता रखा गया है-

* 0-4 किमी- 30 रुपये
* 4-12 किमी- प्रति किमी 23 रुपये
* 12+ किमी- प्रति किमी 18 रुपये

सवारी के विकल्पों में एसी, बिना एसी, बड़ी गाड़ी और प्रीमियम टैक्सी शामिल हैं। बुकिंग के दो मिनट में टैक्सी उपलब्ध होगी। भारत टैक्सी ऐप एंड्रायड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है और अब तक 75,000 से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। ऐप में रियल-टाइम गाड़ी ट्रैकिंग, 24 घंटे ग्राहक सहायता, कई भाषाओं में सपोर्ट और सुरक्षा जांच जैसी सुविधाएँ हैं। कंपनी ओला और उबर जैसी सेवाओं को चुनौती दे रही है।

ड्राइवर एक साथ तीनों प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख स्थानों पर अलग स्टैंड की योजना है।

सीएएफई-3 मानकों पर छोटी कारों को राहत का प्रस्ताव, विवाद पहुंचा पीएमओ तक

- वजन आधारित छूट पर ऑटो उद्योग में गहराया मतभेद

नई दिल्ली ।

आगामी कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (सीएएफई-3) उत्सर्जन मानकों के तहत छोटी कारों को राहत देने के प्रस्ताव को लेकर ऑटोमोबाइल उद्योग में लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) ने इस मुद्दे पर पीएमओ को अलग-अलग पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में भेजे गए पत्रों में दोनों कंपनियों ने कहा कि पेट्रोल से चलने वाली छोटी कारों के लिए वजन के आधार पर नई उप-श्रेणी बनाकर छूट देना देश के इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को कमजोर करेगा। कंपनियों का तर्क है कि इससे सड़क सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है और उन वाहन निर्माताओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने लंबे समय से मौजूदा परिभाषा के अनुरूप निवेश किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रस्तावित बदलाव

से व्यवहारिक रूप से केवल एक ही कार निर्माता को लाभ मिलेगा। फिलहाल नीति के अनुसार, छोटी कारें वे मानी जाती हैं जिनकी लंबाई चार मीटर से कम और पेट्रोल इंजन क्षमता 1,200 सीसी से कम होती है। इसी परिभाषा के आधार पर उद्योग ने अब तक अपने उत्पाद और निवेश योजनाएं तैयार की हैं। सीएएफई फ्रेमवर्क के तहत वाहन निर्माताओं के पूरे फ्लीट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की सीमा (ग्राम प्रति किलोमीटर) तय की जाती है। नियमों के उल्लंघन पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जुर्माना लगा सकता है। मारुति सुजुकी ने अलग से वजन आधारित राहत की मांग की। इसके चलते मतभेद गहराए और सितंबर 2025 में जारी संशोधित ड्राफ्ट में पहली बार 909 किलोग्राम से कम वजन वाली पेट्रोल कारों के लिए 3 ग्राम/किमी अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव शामिल किया गया, जिसने विवाद को और तेज कर दिया।

लोधा डेवलपर्स पर ब्रोकरेज का भरोसा, 77 फीसदी तक रिटर्न की उम्मीद

- आने वाले वर्षों में कंपनी की बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना

नई दिल्ली ।

रियल एस्टेट कंपनी लोधा डेवलपर्स को लेकर देश की दो बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों मोतीलाल ओसवाल और नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने सकारात्मक रुख अपनाया है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की बिक्री और मुनाफे में मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल कंपनी का शेयर बाजार में करीब 1,060-1,080 रुपए के दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन ब्रोकरेज का कहना है कि इसमें आगे अच्छी तेजी की संभावना बनी हुई है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, लोधा डेवलपर्स आने वाले समय में ज्यादा घरों की बिक्री करने की स्थिति में है। कंपनी का कैश फ्लो मजबूत है और ग्राहकों से समय पर भुगतान मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी का कर्ज स्तर भी नियंत्रण में है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति सुरक्षित बनी हुई है। लोधा अब केवल मुंबई क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी पुणे, बैंगलुरु और एनसीआर जैसे बड़े रियल एस्टेट बाजारों में अपने कारोबार का विस्तार कर रही है। पुणे में लोधा की बिक्री तेजी से बढ़ रही है और इस वित्त वर्ष में वहां अच्छा प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। बैंगलरु में शुरुआती

तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की योजना है।

वहीं एनसीआर में भी कंपनी छोटे स्तर पर एंट्री कर भविष्य के अवसर तलाश रही है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारतीय टीम पांचवें टी20 को जीतकर सीरीज समाप्त करने उतरेगी

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। पांच मैचों की इस टी20 सीरीज का चौथा मैच कोहरे और धुंध के कारण रद्द कर दिया गया था। भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका का लक्ष्य किसी भी प्रकार ये मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी पर लाना रहेगा।

वहीं भारतीय टीम के लिए राहत की बात ये है कि अब उसे सीरीज है हारने का खतरा नहीं है। वह अंतिम मैच हारती भी है तो भी सीरीज बराबरी पर ही रहेगी। अब इस अंतिम मैच में सभी की नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर रहेंगी। वह पिछले काफी समय से रन नहीं बना पार रहे। ऐसे में ये इस मैच में अच्छा स्कोर बनाना चाहेंगे। टीम प्रबंधन भी उनके फार्म को लेकर चिन्तित है। सूर्यकुमार ने पिछले 20 मैचों की 18 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। इस दौरान उन्होंने 14.20 के औसत से 213 रन बनाए थे। वहीं उपकप्तान शुभमन गिल का इस मैच में खेलना संदिग्ध है क्योंकि वह पिछले मैच में अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए थे।

ऐसे में उनकी जगह इस मैच में पारी की शुरुआत के लिए संजू सैमसन को अवसर दिया जा सकता है। सैमसन सलामी बल्लेबाज के तौर पर बेहद सफल रहे हैं। शुभमन के आने के बाद उन्हें मध्यक्रम में उतारा जा रहा था पर वह वहां सफल नहीं रहे हैं। ऐसे में इस मैच में वह पारी की शुरुआत करते हुए बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे।

भारतीय टीम का पलड़ा इस मैच में भारी है। उसके पास अच्छे बल्लेबाज व गेंदबाज हैं। टीम के पास हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर होने के साथ ही तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज है।

तेज गेंदबाजी की बात करें तो बांए हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अच्छे फार्म में हर्षित राणा ने भी अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। जसप्रीत बुमराह की भी इस मैच में वापसी होगी। स्पिनर के तौर पर टीम के पास वरुण चक्रवर्ती जैसा गेंदबाज है। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है। ऐसे में बड़ा

स्कोर बनना तय है।

वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात करें तो उसके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है। ऐसे में उसे सीरीज में बराबरी करने बेहतर प्रदर्शन करना होगा। उसकी बल्लेबाजी कप्तान एडेन मार्क्रम के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक , डेविड मिलर पर आधारित रहेगी।

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच में रीजा हेंड्रिक्स की जगह मार्क्रम को शीर्ष क्रम में उतार सकती है। हेंड्रिक्स इस दौरे पर रन नहीं बना पाये हैं। उसके युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका को इस मैच में मार्को यानसन की सेवाएं नहीं मिल पायेंगी। ऐसे में लुंगी एनगिडी और ओटनेल बार्टमैन पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाये तो इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत दर्ज करने हर क्षेत्र में शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करना होगा।

टीमें इस प्रकार हैं

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, शाहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

दक्षिण अफ्रीका : एडेन मार्क्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया, लूथो सिपाम्ला।

बीसीसीआई अब उत्तर भारत में पड़ने वाले मैच स्थलों में बदलाव करेगा: राजीव शुक्ला

-15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के मैच कहीं ओर आयोजित होंगे

एडीलेड (एजेंसी)। मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 रद्द होने से सबक लेते हुए अब आगे के मैचों को लेकर एक महत्वपूर्व फैसला किया है। बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के अनुसार अब 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मुकाबलों को कहीं और आयोजित किया जा सकता है जिससे दर्शकों और खिलाड़ियों को कोई परेशान न हो। इसके साथ ही सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में होने वाले मैचों को कहीं और आयोजित करने पर विचार होगा।

बीसीसीआई को ये बदलाव इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकिक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला कोहरे के कारण रद्द करना पड़ा था। मैच के दिन स्टेडियम में शाम होते-होते दृश्यता इतनी कम हो गई कि अंपायरों को कई बार मैदान का निरीक्षण करना पड़ा। हालात न सुधरने पर आखिरकार मैच को बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया। इस फैसले से हजारों दर्शकों को निराश होकर वापसी लौटना पड़ा। मैच रद्द होने के बाद बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि उत्तर भारत में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाले मैचों के कार्यक्रम को फिर से निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा। शुक्ला के मुताबिक, कोहरा अब सिर्फ अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट को भी प्रभावित कर रहा है, और ऐसे में मैचों को दक्षिण भारत या वेस्ट इंडिया में आयोजित किया जा सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एकदिवसीय सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी जिसके मुकाबले वडोदरा, राजकोट और इंदौर में होने हैं और इसमें भी खराब मौसम से बाधा आ सकती है। वहीं घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक खेली जाएगी, जिसमें जयपुर में भी मैच रखे गये हैं। ऐसे में कोहरे के देखते हुए इन मैचों का आयोजन भी प्रभावित होगा।

लियोन टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने

-टेस्ट इतिहास में छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने

एडीलेड (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने यहां एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरा विकेट लेते ही एक अहम उपलब्धि अपने नाम कर ली है। अब लियोन टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गये हैं। वहीं विश्व स्तर पर टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बने हैं।

उन्होंने इससे पहले नंबर एक पर रहे दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा को सबसे अधिक विकेट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब उनसे आगे केवल दिवंगत महान स्पिनर शेन वॉर्न ही हैं। वार्न ने अपने करियर में 708 विकेट टेस्ट क्रिकेटर में लिए थे।

तीसरे टेस्ट की पहली पारी मे लियोन ने इंग्लैंड के डकेट को बोल्ड कर मैक्ग्रा को विकेट लेने के मामले में तीसरे नंबर पर धकेल दिया। उसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके विकेटों की तादाद 564 पहुंच गई और वह ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इस मैच से पहले तक मैक्ग्रा ने टेस्ट क्रिकेट में 563 विकेट लिए थे। लियोन ने पहले ओली पोप और उसके बाद डकेट को आउट किया।

लियोन अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे इस सूची में श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, भारत के अनिल कुंबले और इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड शामिल हैं। मुरलीधरन ने 800, वॉर्न ने 708, एंडरसन ने 704, कुंबले ने 619 और ब्रॉड ने 604 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं।

'सबसे खराब टेक्नोलॉजी' : एडिलेड टेस्ट में स्निको विवाद पर मिशेल स्टार्क का तीखा हमला

नई दिल्ली (एजेंसी)। एशेज सीरीज के एडिलेड टेस्ट में अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी एक बार फिर बड़े विवाद की वजह बन गई। दूसरे दिन लगातार दो फैसलों ने खिलाड़ियों और दर्शकों, दोनों को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क ने स्निको टेक्नोलॉजी पर खुलकर नाराज़गी जताते हुए इसे 'सबसे खराब टेक्नोलॉजी' करार दिया और यहां तक कह दिया कि इसे हटाने की ज़रूरत है। विवादित फैसलों के बीच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही खेमों में असंतोष साफ दिखाई दिया।

पहला विवाद: स्मिथ के हेलमेट पर लगी गेंद, फिर भी स्निको स्पाइक

विवाद की शुरुआत तब हुई जब पैट कमिंस की एक तेज़ शॉर्ट बॉल इंग्लैंड के बल्लेबाज़ स्मिथ पर अजीब उछाल लेकर आई। स्मिथ ने खुद को बचाने की कोशिश की और गेंद फर्स्ट स्लिप की ओर गई, जहां उस्मान ख्वाजा ने आगे की ओर डाइव लगाई।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने ज़ोरदार अपील की, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर को संदेह था कि गेंद बल्ले या ग्लव्स से लगी है या नहीं। मामला थर्ड अंपायर के पास गया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्मिथ के हेलमेट से टकराई थी, इसके बावजूद स्निको मीटर में स्पाइक नजर आया। अंततः फैसला नॉट-आउट रहा, लेकिन इसी स्पाइक ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया।

'स्निको को हटाने की जरूरत'

इस फैसले के बाद मिशेल स्टार्क को स्टंप माइक पर अंपायर से चर्चा करते हुए सुना गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्निको टेक्नोलॉजी भरोसेमंद नहीं रही है। स्टार्क ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी पहले भी गलत साबित हो चुकी है और एक बार फिर खिलाड़ियों को भ्रमित कर रही है। उनके मुताबिक, ऐसे अहम टेस्ट मैच में इतनी बड़ी गलती स्वीकार्य नहीं है।

दूसरा झटका: जेमी स्मिथ का विवादित आउट

पहले विवाद की गर्मी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जेमी स्मिथ के आउट होने पर एक और बहस छिड़ गई। पैट कमिंस की शॉर्ट गेंद पर स्मिथ ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन संपर्क साफ नहीं था। गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी तक पहुंची और अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर को भेजा। हालांकि वीडियो रिप्ले में बल्ले और गेंद के बीच साफ गैप नजर आ रहा था, लेकिन गेंद के बल्ले के पास से गुजरते ही स्निको में एक स्पाइक दर्ज हुआ। इसी आधार पर थर्ड अंपायर ने स्मिथ को आउट करार दे दिया।

बेन स्टोक्स ने टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाए

इस फैसले के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स काफी नाराज़ दिखे। उनका मानना था कि सिर्फ स्निको स्पाइक के आधार पर फैसला देना सही नहीं है, खासकर तब जब वीडियो

सबूत कुछ और कहानी बता रहे हों। मैच में DRS का इस्तेमाल न होने के बावजूद, थर्ड अंपायर का फैसला पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहा, जिसने बहस को और तेज कर दिया।

स्निको टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता पर बहस

एडिलेड टेस्ट की घटनाओं ने एक बार फिर स्निको टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेटर और फैंस अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या सिर्फ ऑडियो स्पाइक के आधार पर बड़े फैसले लेना सही है।

स्पेनिश टेनिस स्टार अल्काराज ने कोच फेरेरो से नाता तोड़ा

मैड्रिड। दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने अपने कोच जुआन कार्लोस फेरेरो के साथ चली आ रही सात साल की साझेदारी को समाप्त कर दिया है। नये साल की शुरुआत से सैमुअल लोपेज, अल्काराज के नये कोच होंगे। 22 साल के स्पेनिश खिलाड़ी ने फेरेरो के साथ तब काम करना शुरू किया था जब वह 15 साल के थे। फेरेरो के मार्गदर्शन में वह रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे और कुल छह ग्रैंड स्लैम खिताब और 22 टूर्नामेंट जीते। अल्काराज ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच पर जारी एक बयान में बताया, 'हम शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर हमारे खेल के रास्ते अलग होने हैं, तो यह तब होना चाहिए जब हम सबसे ऊंचे मुकाम पर हों। वह मुकाम जिसके लिए हमने हमेशा प्रयास किया और हमेशा वहां पहुंचने की उम्मीद की।' स्पेनिश स्पोर्ट्स अखबार डियारियो एएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाब्लो कैरेनो बुस्टा को कोचिंग देने वाले सैमुअल लोपेज 2026 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी के लिए अल्काराज के नए कोच होंगे।

धोनी से सीखना चाहते हैं प्रशांत

मुम्बई । आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में 14.2 करोड़ रुपये हासिल करने वाले अनकैप्ड ऑलराउंडर प्रशांत वीर का सपना चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के साथ खेलना और सीखना है। प्रशांत का कहना है कि वह धोनी के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से खेलने वाले प्रशांत वीर को सीएसके ने नीलामी में 14.2 करोड़ में खरीदा है। प्रशांत ने कहा कि वह चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़कर बेहद खुश हैं क्योंकि वहां एमएस धोनी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि धोनी जिस तरह से निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। उनकी मानसिक मजबूती बातचीत का तरीका और खेल के दौरान उनका ध्यान ये सभी चीजें सीखने लायक हैं। उन्होंने अंत में कहा, 'अगर मैं उन जैसे महान खिलाड़ी से 4 से 5 फीसदी भी सीख पाता हूं, तो वह मेरे करियर के लिए बहुत सहायक होगा।' सीएसके ने प्रशां के अलावा कार्तिक शर्मा को भी 14.2 करोड़ में खरीदा है। जिससे ये दोनो ही आईपीएल के सबसे महंगे गैरअनुभवी खिलाड़ी बन गये हैं। कार्तिक के लिये भी सीएसके और हैदराबाद के बीच खींचतान हुई, लेकिन आखिरकार चेन्नई की फ्रेंचाइज़ी ने इस विस्फोटक बल्लेबाज को 14.2 करोड़ में खरीद लिया। ये दोनों ही खिलाड़ी लीग के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गये। इससे पहले यह रिकॉर्ड आवेश खान के पास था जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 में 10 करोड़ में खरीदा था।

पीएसजी ने फ्लेमेंगो को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता

दोहा (कतर) (एजेंसी)। पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में ब्राज़ील की फ्लेमेंगो टीम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यह पीएसजी की इस साल की छठी बड़ी ट्रॉफी है, जिससे क्लब का सुनहरा सीजन और भी यादगार बन गया।

अल रेयान स्थित अहमद बिन अली स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल में निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद स्कोर 1-1 से बराबर रहा। इसके बाद हुए पेनल्टी शूटआउट में पीएसजी ने फ्लेमेंगो को 2-1 से मात देकर खिताबी जीत दर्ज की।

रोमांचक रहा फाइनल मुकाबला

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक रुख अपनाया। पीएसजी को पहला गोल 38वें मिनट में ख्विचा क्रारात्सखेलिया ने दिलाया, जिससे फ्रेंच क्लब ने बढ़त हासिल की। हालांकि, हाफटाइम के बाद फ्लेमेंगो ने जोरदार वापसी की। 62वें मिनट में जोर्जिन्हो ने पेनल्टी को गोल में बदलते हुए स्कोर बराबर कर दिया।

इसके बाद दोनों टीमों को कई मौके मिले, लेकिन गोल करने में सफलता नहीं मिली। मैच के अंतिम क्षणों में पीएसजी गोल के बेहद करीब पहुंचा, मगर फ्लेमेंगो के गोलकीपर ऑगस्टिन रॉसी ने शानदार बचाव कर टीम को बचाए रखा।

शूटआउट में पीएसजी का दबदबा

निर्धारित समय और अतिरिक्त समय में कोई गोल नहीं होने के बाद मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। यहां पीएसजी के खिलाड़ियों ने बेहतर संयम दिखाया और फ्लेमेंगो को 2-1 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

पीएसजी का सुनहरा सीजन

फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने के साथ ही पीएसजी ने इस साल अपनी छठी ट्रॉफी हासिल की। इससे पहले क्लब ने लीग 1, कूप डी फ्रांस, ट्रॉफी डेस चैंपियंस, यूईएफए चैंपियंस लीग और यूईएफए सुपर कप के खिताब भी अपने नाम किए थे।

यह जीत पीएसजी के लिए न सिर्फ एक और ट्रॉफी है, बल्कि उनके ऐतिहासिक और सफल सीजन की पुष्टि भी करती है।

फ्रांस के पूर्व स्ट्राइकर हेनरी को मिलेगा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

लंदन। आर्सेनल और फ्रांस के पूर्व स्ट्राइकर थियरी हेनरी को 2025 के बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कार्यक्रम में आज लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। 2014 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने वाले हेनरी ने इस पुरस्कार से सम्मानित किये जाने को लेकर कहा कि यह सम्मान मिलना बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा, 'फुटबॉल ने मुझे सब कुछ दिया है और मैंने भी इसे अपना सब कुछ दिया है। इस लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड के साथ इसके इतिहास का हिस्सा बनने के लिए पहचाना जाना, और फैंस और मेरे टीम के साथियों के लिए अपनी पहचान बनाना, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी हल्के में नहीं लूंगा।' आर्सेनल के साथ दो बार खेलते हुए, हेनरी ने 377 मैचों में 228 गोल किए, और 2005 में इयान राइट को पीछे छोड़कर क्लब के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बन गए। गनर्स के साथ उनके सम्मानों में दो प्रीमियर लीग खिताब और तीन एफए कप शामिल हैं, जिसमें सबसे खास 2003-04 का सीजन था जब आर्सेनल अजेय रहा और 'इनविंसिबल' का दर्जा हासिल किया। हेनरी ने चार बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता, जो एक संयुक्त रिकॉर्ड है और लगातार 6 सीजन तक पीएफए टीम ऑफ द ईयर में नामित हुए।

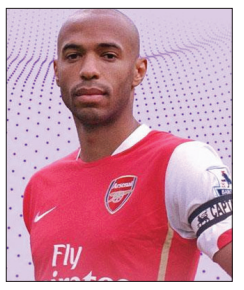

श्रीलंकाई टीम के क्षेत्ररक्षण कोच होंगे श्रीधर

कोलंबो। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने भारत के आर श्रीधर को को आगामी टी20 विश्वकप कप के लिए अपनी टीम का क्षेत्ररक्षण कोच बनाया है। श्रीधर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के लेवल 3 क्वालिफाइड कोच हैं। श्रीधर इससे पहले साल 2014 से 2021 तक भारत की पुरुष टीम के क्षेत्ररक्षक कोच रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान टीम के साथ भी सलाहकार के तौर पर काम किया। अब वह श्रीलंकाई टीम के क्षेत्ररक्षण को सुधारने की जिम्मेदारी संभालेंगे। वह पाकिस्तान और इंग्लैंड के आगामी दौरों पर टीम के साथ मिलकर काम करेंगे और फिर टी-20 विश्व कप की तैयारियों की देखरेख करेंगे। वहीं श्रीधर ने इस जिम्मेदारी पर उत्साहित होते हुए कहा, श्रीलंकाई खिलाड़ी हमेशा सहज प्रतिभा वाले होने के साथ ही सामूहिक रुप से खेलने पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। मेरा काम उनपर किसी प्रकार का नया दबाव बनाना नहीं है। वहीं ऐसा माहौल बनाना है जहां खिलाड़ी अपनी क्षमता, जागरूकता के क साथ मैदान पर स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा, फील्डिंग तब बेहतर होती है जब खिलाड़ी गेंद से, एक-दूसरे से और उस पल से जुड़ाव महसूस करते हैं। श्रीलंका की पारंपरिक ताकतें तेज हाथ, तेज रिफ्लेक्स और निडर इरादा रहा है। इन्हीं क्षमताओं को और निखारा जाएगा। वहीं श्रीलंकाई बोर्ड ने कहा है कि श्रीधर के आने से टीम का प्रदर्शन बेहतर होने का उन्हें भरोसा है।

आईपीएल 2026 : नीलामी में नहीं बिके ये बड़े खिलाड़ी, आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 की नीलामी में जहां करोड़ों की बोली और नए सितारों के उभार ने सुर्खियां बटोरीं, वहीं कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय नामों का ना बिकना क्रिकेट जगत के लिए हैरानी भरा रहा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर विश्लेषक आकाश चोपड़ा ने माइकल ब्रेसवेल, जेमी स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को किसी भी टीम द्वारा नहीं खरीदे जाने पर खुलकर सवाल उठाए। उनका मानना है कि इस बार नीलामी में कई फैसलों ने क्रिकेट लॉजिक को पीछे छोड़ दिया।

आकाश चोपड़ा को क्यों हुआ सबसे ज्यादा आश्चर्य?

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर आईपीएल ऑक्शन को लेकर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफघरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बड़ा इनाम मिला, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित कर चुके खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया। चोपड़ा के मुताबिक यह नीलामी कई मायनों में ÷सरप्राइज पैकेज÷ रही।

माइकल ब्रेसवेल: ऑलराउंडर, फिर भी अनसोल्ड

न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल को लेकर आकाश चोपड़ा सबसे ज्यादा हैरान दिखे। उन्होंने याद दिलाया कि ब्रेसवेल भारत के खिलाफबड़े मैचों में शतक जड़ चुके हैं और वह बल्लेबाजी के साथ-साथ ऑफस्पिन भी कर सकते हैं। आकाश का मानना था कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमों को ऐसे खिलाड़ी की सख्त जरूरत थी, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। टी20आई में संतुलित रिकॉर्ड और बड़े मैचों का अनुभव होने के बावजूद उनका अनसोल्ड रहना कई सवाल खड़े करता है।

जेमी स्मिथ: विकेटकीपर-बल्लेबाज, फिर भी मौका नहीं

इंग्लैंड के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ को लेकर भी आकाश चोपड़ा ने 'लॉजिक फेल' करार दिया। उन्होंने कहा कि स्मिथ को कई बार नीलामी में लाया गया, यहां तक कि एक्सेलरेटेड राउंड तक पहुंचे, लेकिन हर बार टीमों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आकाश के मुताबिक जेमी स्मिथ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों में बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट और फिनिशिंग एबिलिटी टी20 क्रिकेट के लिए आदर्श मानी जाती है, फिर भी किसी फ्रेंचाइजी ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया।

जॉनी बेयरस्टो का अनसोल्ड रहना सबसे बड़ा झटका

इंग्लैंड के अनुभवी स्टार जॉनी बेयरस्टो का

नाम अनसोल्ड लिस्ट में होना आकाश चोपड़ा के लिए सबसे चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कहा कि जब टिम सीफर्ट, फिन एलन, क्विंटन डी कॉक और बेन डकेट जैसे बल्लेबाज बिक सकते हैं, तो बेयरस्टो के लिए जगह न बनना समझ से बाहर है। पिछले सीजन में सीमित मौकों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने वाले बेयरस्टो अगर पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहते, तो किसी भी टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते थे।

बाबर आजम बीबीएल में भी असफल हुए, प्रशंसकों ने जमकर हूटिंग की

लाहौर। पिछले काफी समय से खराब फार्म से जूझ रहे पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम आजकल ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग (बीबीएल) खेल रहे हैं। बाबर वहां भी असफल रहे हैं। वह अपने शुरुआती मैच में 5 गेंदों में केवल 2 रन ही बना पाये। जिसके बाद से ही उनकी आलोचनाएं शुरु हो गयी हैं। लगातार दूसरे मैच में असफल होने पर प्रशंसकों ने उनका मजाक बताया है। इसी कारण आउट होने के बाद जब बाबर पवेलियन लौट रहे थे तो प्रशंसकों ने उनकी काफी हूटिंग की। बाबर ने यहां सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेलते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 10 गेंदों में केवल 9 रन ही बनाये। इससे उनके प्रशंसक भड़क गये। पहले दो मैचों में ही उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है जिससे अब तीसरे मैच में उन्हें शायद ही अवसर मिले। इससे उनके टी20 विश्वकप के लिए टीम में जगह पक्की करने की दावेदारी भी कमजोर हुई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

बांग्लादेश के दूतावास में मनाया गया विजय दिवस, उच्चायुक्त बोले- भारत के साथ संबंध लाभकारी

ढाका, एजेंसी। दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास में विजय दिवस एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। बांग्लादेशी उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह ने बांग्लादेश की जनता, खासकर युवाओं, की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। हमीदुल्लाह ने कहा कि बांग्लादेश और भारत का आपसी संबंध लाभकारी है, जो समृद्धि, शांति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, पूरा बांग्लादेश और हम सभी अपनी जनता, खासकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी आबादी बहुत युवा है... हम मानते हैं कि भारत के साथ हमारा संबंध हमारे साझा हित में है। हमारे बीच आपसी निर्भरता है... हम क्षेत्र में समृद्धि, शांति और सुरक्षा पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। कार्यक्रम में बांग्लादेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दिखाया गया और इसके स्वतंत्रता संग्राम और आजादी का जश्न मनाया गया।

गाजा में मूसलाधार बारिश जारी, विस्थापित परिवारों पर टूटा कहर

गाजा , एजेंसी। गाजा में कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। भारी बारिश से विस्थापितों के शिविर जलमग्न हो गए, पहले से क्षतिग्रस्त इमारतें ढह गईं और कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में दो सप्ताह का एक नवजात भी शामिल है, जिसकी ठंड लगने से मौत हुई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बच्चे को कुछ दिन पहले अस्पताल लाया गया था और आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई। गाजा सिटी में एक और व्यक्ति की जान तब चली गई, जब बारिश के कारण इस्राइली हमलों में क्षतिग्रस्त एक घर गिर गया। बीते एक हफ्ते में कुछ इलाकों में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे कच्चे रास्ते कीचड़ में बदल गए और तंबुओं में पानी भर गया। आपातकर्मियों ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की है, लेकिन गाजा में सुरक्षित ठिकानों की भारी कमी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हैं। दो महीने से जारी युद्धविराम के बावजूद राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही है। अधिकतर लोग समुद्र तट के पास तंबुओं में या टूटी इमारतों के बीच रह रहे हैं, जहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इस्राइली एजेंसी कोगाट ने दावा किया कि लाखों टेंट और सर्दियों का सामान भेजा गया है, लेकिन राहत संगठनों का कहना है कि जरूरत के मुकाबले मदद बहुत कम है और ठंड से बचाव के साधन बेहद अपर्याप्त हैं।

पाकिस्तान के सिंध में बंदूकधारियों ने 18 बस यात्री अगवा कर लिए

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने बस में क्वेटा जा रहा 18 यात्रियों को अगवा कर लिया। घटना सोमवार रात घोटकी के पास घटी, जब हमलावरों ने सिंध-पंजाब सीमा के करीब हाईवे लिंक रोड पर बस पर गोलियां चलाईं। गोलीबारी में चालक व कुछ यात्री घायल हो गए। एक महिला यात्री ने बताया कि घटनास्थल पर कुल 18 से 20 हमलावर मौजूद थे, सभी हथियारबंद थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने महिला यात्रियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई।

पाकिस्तान में पोलियो टीम पर हमला, पुलिसकर्मी की हुई हत्या

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पोलियो टीकाकरण अभियान से जुड़े सुरक्षा कर्मियों पर एक और घातक हमला सामने आया है। मंगलवार को लक्की मरवत जिले के छ्वार खेल इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने मोटरसाइकिल से आकर एक पुलिस कांस्टेबल और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, कांस्टेबल पोलियो टीकाकरण टीम के साथ ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने भाई के साथ गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में कांस्टेबल अमीर नवाज और उसके भाई अमीर मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पूर्व जिला पार्षद अली गुल के भाई बताए गए हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। शाम को दोनों मृतकों की जनाजे की नमाज अदा की गई, जिसमें जिला पुलिस अधिकारी नजीर खान, डिप्टी कमिश्नर हमीदुल्लाह खान, एसपी जांच मुराद अली खान समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इससे पहले इसी दिन बाजौर जिले में भी पोलियो ड्यूटी पर तैनात एक अन्य पुलिस कांस्टेबल और एक राहगीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगातार हो रहे इन हमलों ने पाकिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 और देशों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध बढ़ाया

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंधों को और सख्त करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 20 और देशों के साथ-साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी प्रतिबंध सूची में जोड़ दिया गया है। इस कदम से अमेरिका आने या इमिग्रेट करने वालों पर लगाई गई सीमाएं काफी बढ़ गई हैं। अब कुल पांच देशों पर अमेरिका में प्रवेश का पूरी तरह प्रतिबंध है। वहीं 15 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक लगाई गई है। प्रशासन ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करने वाले लोगों की यात्रा पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम अमेरिका में प्रवेश से जुड़े नियमों को और कड़ा करने के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। अधिकारियों ने हाल ही में व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड जवानों पर गोलीबारी के आरोपी एक अफगान नागरिक की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया।हालांकि, इन प्रतिबंधों में कुछ छूट भी दी गई है। जिन लोगों के पास पहले से वैध

अमेरिकी वीजा है, उन पर यह रोक लागू नहीं होगी। स्थायी निवास की अनुमति वाले लोग, राजनयिक, खिलाड़ी और कुछ अन्य श्रेणियों के वीज़ा धारक भी इससे बाहर रखे गए हैं। अगर किसी व्यक्ति का प्रवेश अमेरिका के हित में माना गया, तो उसे अनुमति मिल सकती है। सरकार ने यह नहीं बताया है कि ये नए नियम कब से लागू होंगे।

ट्रंप ने पहली बार ऐसे यात्रा प्रतिबंध जून में लगाए थे। तब 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश से पूरी तरह रोका गया था और सात देशों पर आंशिक पाबंदी लगाई गई थी। यह नीति ट्रंप के पहले कार्यकाल की चर्चित नीति की याद दिलाती है। जून के प्रतिबंध में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल थे। बुरुंडी, क्यूबा, ??लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए थे। मंगलवार को, प्रशासन ने बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया को पूर्ण-प्रतिबंध सूची में जोड़ा। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के दस्तावेजों पर भी पूरी रोक लगा दी गई है। दक्षिण सूडान पहले से ही कड़े प्रतिबंधों में था। आंशिक प्रतिबंध की सूची में 15 नए देश जोड़े गए हैं। इनमें अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंज़ानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

ये प्रतिबंध घूमने आने वाले लोगों और स्थायी रूप से बसने की कोशिश करने वालों, दोनों पर लागू होंगे।

अपने आदेश में ट्रंप ने कहा कि इन देशों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकारी दस्तावेज अविश्वसनीय हैं और अपराध से जुड़े रिकॉर्ड ठीक से उपलब्ध नहीं हैं। इससे यात्रियों की सही जांच करना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने यह भी कहा कि कई देशों के नागरिक वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं और कुछ देश अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर देते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि कुछ देशों में अस्थिरता और कमजोर शासन व्यवस्था है, जिससे सुरक्षा, विदेश नीति और आव्रजन से जुड़े खतरे बढ़ते हैं। इस बीच, लाओस और सिएरा लियोन को आंशिक रोक से हटाकर पूरी रोक वाले देशों में डाल दिया गया है। वहीं तुर्कमेनिस्तान पर लगाए गए प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है, क्योंकि वहां सुधार बताए गए हैं। जून में घोषित बाकी सभी प्रावधान अभी भी लागू हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी यात्रा प्रतिबंध बड़ा मुद्दा रहे थे, जिनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियां शुरू हुई थी। बाद में अदालतों ने संशोधित नियमों को सही ठहराया। समर्थकों का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होती है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह लोगों को उनके देश के आधार पर अनुचित रूप से निशाना बनाता है।

कनाडाई शिष्टमंडल के वेस्ट बैंक जाने पर रोक, इस्राइल का आरोप- आतंकी संगठन से संबंध

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल ने मंगलवार को कनाडा से आए एक निजी प्रतिनिधिमंडल को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में प्रवेश करने से रोक दिया। इस दल में कनाडा की संसद के छह सदस्य (सांसद) शामिल थे। कनाडा में इस्राइल के दूतावास ने कहा कि इस समूह को इसलिए रोका गया क्योंकि इसके कुछ संबंध इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड नाम की संस्था से बताए जा रहे हैं। इस्राइल इस संस्था को आतंकी संगठन मानता है। इस मामले पर कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने सोशल मीडिया पर कहा कि कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों, खासकर सांसदों, के साथ हुए इस बर्ताव पर आपत्ति जताई है।

इतना ही नहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी की ओंटारियो से सांसद इकरा खालिद ने सीमा पर खड़े इस्राइली सुरक्षाकर्मियों पर धक्का-मुक्की का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वह भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्राइली सीमा अधिकारियों ने उन्हें कई बार धक्का दिया।

दावा- इस्राइली अधिकारियों ने सांसदों को दिया धक्का : मामले में इकरा खालिद ने कहा कि जब वह अपने दल के एक सदस्य की मदद के लिए आगे बढ़ीं, तब उन्हें धक्का दिया गया। यह घटना एलनबी बॉर्डर क्रॉसिंग पर हुई, जो जॉर्डन और इस्राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के

बीच स्थित है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को पता था कि वह सांसद हैं, क्योंकि उनके पास विशेष सरकारी पासपोर्ट था, जो आम कनाडाई पासपोर्ट से अलग दिखता है।

अब समझिए क्या है इस्राइल का पक्ष : वहीं इस घटना पर इस्राइली दूतावास ने बताया कि इस्राइल उन लोगों और संगठनों को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, जिनका संबंध घोषित आतंकी संगठनों से है। इस प्रतिनिधिमंडल को 'कनाडाई-मुस्लिम वोट' नाम के संगठन ने प्रायोजित किया था। यह समूह वेस्ट बैंक में विस्थापित फलस्तीनियों से मिलने वाला था। इस्राइल का कहना है कि इस संगठन को ज्यादातर फंडिंग इस्लामिक रिलीफ कनाडा से मिलती है, जो इस्लामिक रिलीफ वर्ल्डवाइड से जुड़ा हुआ है। इस्राइल इस पूरी संस्था को आतंकी संगठन मानता है। वहीं इस मामले में कनाडा में नेशनल काउंसिल ऑफ कनाडियन मुसलिम्स ने कहा कि इस्राइल द्वारा कनाडा के सांसदों को प्रवेश न देने से पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

मोजांबिक के राष्ट्रपति से मिली जॉर्जिया मेलोनी; हाइट में अंतर वाली तस्वीर वायरल

रोम, एजेंसी। इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मोजांबिक के राष्ट्रपति डेनियल फ्रांसिस्को चापो से पिछले हफ्ते रोम में हुई मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हाइट के बड़े अंतर ने सबका ध्यान खींच लिया। मेलोनी राष्ट्रपति चापो से मिलने आगे बढ़ीं तो ऊपर देखकर थोड़ा हैरान हो गईं, फिर शरमाते हुए मुस्कुराईं और फोटो खिंचवाने के लिए पोज किया।

48 साल के राष्ट्रपति चापो की लंबाई करीब 6 फुट 8 इंच है, जबकि मेलोनी की लंबाई करीब 5 फुट 2 इंच है। इस बड़े अंतर की वजह से फोटोग्राफर्स को दोनों को एक ही फ्रेम में कैद करने में काफी मुश्किल हुई, कई फोटोग्राफर्स झुक गए, तो कुछ जमीन पर लेटकर तस्वीरें लेने लगे।

राष्ट्रपति चापो बास्केटबॉल के शौकीन हैं और पहले भी अन्य विश्व नेताओं के साथ तस्वीरों में अपनी लंबाई की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। यह बैठक मोजांबिक की आजादी की 50वीं वर्षगांठ और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग पर बात की। इस प्लान में ऊर्जा तक पहुंच, सतत कृषि, व्यावसायिक प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने जैसे कई संयुक्त प्रोजेक्ट शामिल हैं।

नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फिर टला लंदन कोर्ट का फैसला, मार्च 2026 में होगी अगली सुनवाई

लंदन, एजेंसी। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े करीब 2 अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में एक बार फिर देरी हो गई है. लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की उस अर्जी पर सुनवाई मार्च 2026 तक के लिए टाल दी है, जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को दोबारा खोलने की अनुमति मांगी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह बात सामने आई कि नीरव मोदी द्वारा प्रत्यर्पण रोकने के लिए अपनाया गया कोई 'गोपनीय कानूनी रास्ता' (संभवतः शरण की अर्जी) अगस्त में विफल हो गया है. इसके तुरंत बाद उसने अपनी अपील को दोबारा खोलने की यह नई याचिका दायर की. भारत की 'मजबूत गारंटी' और कोर्ट का

रुख लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की पीठ ने सुनवाई की. भारतीय अधिकारियों (सीबीआई और ईडी) ने नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखने और उससे पूछताछ को लेकर 'पुख्ता संप्रभु आश्वासन' पेश किए.

मार्च 2026 में होगी अगली सुनवाई : हालांकि, नीरव के वकीलों ने दावा किया कि ये आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं और भारत में उनके मुवक्किल के साथ 'अमानवीय व्यवहार' का खतरा है. अदालत ने नीरव के वकीलों को इन आश्वासनों का जवाब देने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई मार्च 2026 तक टाल दी.

जज ने इस देरी पर टिप्पणी करते हुए इसे 'बेहद निराशाजनक' बताया. अगर मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाली दो दिवसीय सुनवाई में नीरव की अर्जी खारिज हो जाती है, तो उसके प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा. नीरव मोदी, जो इस समय उत्तरी लंदन की पेंटनविल जेल में बंद है, वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुआ. कोर्ट ने तय किया कि अब यह मामला 'रोल्ड-अप हियरिंग' के तौर पर सुना जाएगा, जिसमें यह तय होगा कि अपील दोबारा खोलने की अनुमति दी जाए या नहीं. नीरव मोदी के वकीलों ने संजय भंडारी केस का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत में उसे अमानवीय व्यवहार का खतरा है. हालांकि, भारतीय पक्ष ने इस तुलना को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि नीरव मोदी के मामले में पहले से ही पर्याप्त और विश्वसनीय आश्वासन दिए जा चुके हैं. आपको बता दें कि नीरव मोदी पर भारत में तीन बड़े आपराधिक मामले चल रहे हैं- पीएनबी बैंक घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों से छेड़छाड़. साल 2019 में गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार कानूनी रास्तों से प्रत्यर्पण टालने की कोशिश करता रहा है.

वॉट्सऐप का विकल्प लाया पाकिस्तान, सरकारी कर्मचारी अब करेंगे 'बीप'; चीन से क्या कनेक्शन

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान ने सुरक्षा और खुफिया चिंताओं के चलते वॉट्सऐप का विकल्प तैयार कर लिया है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि वॉट्सऐप पर मेसेज भेजने और जरूरी दस्तावेजों को शेयर करने से खुफिया खतरे हैं। ऐसी स्थिति में हम एक स्थानीय स्तर पर तैयार ऐप 'बीप' लेकर आ रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म अगले दो महीने में ही लॉन्च हो सकता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि जून, 2026 तक यह ऐप पूरे देश के कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा। इस ऐप को चीन के वीचैट ऐप की तर्ज पर तैयार किया गया है। पाकिस्तान के नेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ओर से इसे स्थानीय स्तर पर ही तैयार किया गया है।

इसे आधिकारिक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। कमेटी के चेयरमैन सैयद अमिनुल हक का कहना है कि इस ऐप से सरकारी कर्मचारियों की सूचनाओं को सुरक्षा मिलेगी। किसी दूसरे देश तक हमारी संवेदनशील जानकारियां नहीं पहुंच सकेंगी। उन्होंने कहा कि क्ष्क्षश्वक्ष्क को तैयार करने की वजह यह है कि वॉट्सऐप का सर्वर दूसरे देश में स्थित है। ऐसे में जानकारी लीक होने और जासूसी के खतरे बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक स्थानीय ऐप हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। चीन तो सालों से ऐसी ही नीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इस ऐप को चरणबद्ध तरीके से अलग-अलग विभागों में लागू किया जाएगा।

मेटा के मालिकाना हक वाले वॉट्सऐप को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताई जाती रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वॉट्सऐप पर सरकारी संस्थानों के लोग वॉइस कॉल करते हैं। वीडियो कॉल किए जाते हैं और मीडिया शेयरिंग भी होती है। लेकिन इसके डेटा सर्वर देश से बाहर हैं। बीप के सर्वर पाकिस्तान में होंगे। इसलिए उसकी सुरक्षा तय हो सकेगी। पाकिस्तान सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस ऐप को हमने चीन के वीचेट की तर्ज पर तैयार किया है। सरकारी कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय और सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए इस ऐप को अहम माना जा रहा है।

'ड्रग्स लेते थे मस्क, हर घटना के पीछे साजिश देखते हैं वेंस', अमेरिकी अफसर का दावा

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी सूसी वाइल्स ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब लोगों के बारे में स्पष्ट और आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क केटामाइन (ड्रग) का सेवन करते थे। उन्होंने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस को 'बिना सबूतों के हर बड़ी घटना के पीछे गोपनीय साजिश मानने वाला व्यक्ति' और बजट प्रमुख रस वॉट को 'कट्टर दक्षिणपंथी' बताया। उन्होंने जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को संभालने के तरीके को लेकर अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी की भी आलोचना की। इस इंटरव्यू के सामने आने के व्हाइट हाउस ने उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, सूसी वाइल्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस खबर में जरूरी संदर्भों को नजरअंदाज किया गया और इसे जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने सूसी वाइल्स का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रंप के पास सूसी से बड़ा या उनसे ज्यादा वफादार सलाहकार कोई नहीं है। लीविट ने एक्स पर कहा, 'पूरा प्रशासन उनके स्थिर नेतृत्व के लिए आभारी है और पूरी तरह उनके साथ खड़ा है।' लेकिन यह इंटरव्यू फिर से राष्ट्रपति और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर सकता है और पुराने मतभेद, खासकर मस्क के साथ फिर से टकराव पैदा कर सकता है। वाइल्स ने मस्क के बारे में कहा, वह पूरी तरह अकेले काम करने वाले व्यक्ति हैं। एलन के साथ चुनौती यह है कि उनकी गति के साथ कदम मिलाना मुश्किल है। जब उनसे पूछा गया कि मस्क ने एक्स पर जो पोस्ट शेयर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी एडॉल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और माओ जेदोंग के समय लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार थे, इसके बारे में उनका क्या विचार है, तो वाइल्स ने कहा, मुझे लगता है उस समय वह हल्का ड्रग (माइक्रोडोजिंग) का इस्तेमाल कर रहे थे।

नेतन्याहू से मिले एस जयशंकर, भारत और इस्राइल की साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर जोर

तेल अवीव, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इस्राइल के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा भारत और इस्राइल के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा कि भारत और इस्राइल की रणनीतिक साझेदारी आगे और मजबूत होगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी दीं है। जयशंकर और नेतन्याहू ने तकनीक, आर्थिक क्षेत्र, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। नेतन्याहू ने भी जयशंकर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काम जारी रहेगा।

निर बरकास से की मुलाकात : पीएम के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यरूशलम में इस्राइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री निर बरकात से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच निवेश, नवाचार और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने भरोसा जताया कि भारत-इस्राइल मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होगा, जिससे आर्थिक साझेदारी को नई गति मिलेगी। दो दिन के इस्राइल दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत की। उन्होंने इस्राइल के विदेश मंत्री गिडियन साअर, राष्ट्रपति इसहाक हरजोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्तावित भारत दौरे की तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद इस्राइली प्रधानमंत्री ने जल्द

मुलाकात का संकेत दिया था।

एफटीए से निवेश और नवाचार को बढ़ावा : जयशंकर ने निर बरकात के साथ बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों ने निवेश और नवाचार सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत-इस्राइल मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होने से आर्थिक साझेदारी को बड़ा लाभ मिलेगा। दोनों देश तकनीक, स्टार्टअप, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक हैं और इसका लाभ उठाने की जरूरत है।

आतंकवाद पर भारत-इस्राइल की सख्त नीति : जयशंकर ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत और इस्राइल दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। जयशंकर ने इस्राइल को भारत के आतंकवाद विरोधी संघर्ष में लगातार समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप के खिलाफ दोनों देश एकजुट हैं।

रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय शांति : विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत-इस्राइल रणनीतिक साझेदारी काफी मजबूत हुई है। इसमें सरकार से सरकार, कारोबार से कारोबार और लोगों से लोगों के बीच संपर्क शामिल है। जयशंकर ने गाजा शांति योजना के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया और उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी और टिकाऊ शांति का रास्ता खुलेगा। उच्चस्तरीय दौरे और बढ़ता सहयोग जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों देशों के बीच लगातार उच्चस्तरीय आदान-प्रदान हो रहा है। इस साल इस्राइल के कई मंत्री भारत आ चुके हैं। हाल ही में दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए और प्रस्तावित एफटीए के लिए नियम तय किए गए। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने उन्नत तकनीक साझा करने और सह-विकास पर अहम समझौता किया है। जयशंकर इससे पहले अबू धाबी में सर बनी यास फोरम में शामिल हुए थे और भारत-यूएई संयुक्त आयोग की बैठक में भी भाग लिया था। इस्राइल दौरे के बाद उनके कार्यक्रम से साफ है कि भारत पश्चिम एशिया में अपने रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और गहराई देना चाहता है। भारत-इस्राइल साझेदारी आने वाले समय में व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की दिशा में बढ़ रही है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

वीबी- जी राम जी बिल बहुत बड़ा विश्वासघात इसे वापस लेना होगा : संजय सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी- जी राम जी बिल लोकसभा में गुरुवार को पारित हो गया है। ये बिल यूपीए दौर की मनरेगा योजना की जगह लेगा। इस बिल पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानूनों को वापस लिया वैसे ही आपको इस बिल को भी वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में इसके ख़िलाफ़ आंदोलन होगा। इस बिल के नाम के पीछे आप अपना गुनाह छिपाना चाहते हैं। मनरेगा और केंद्र सरकार के नए अधिनियम में नाम के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं और विपक्षी दल सरकार के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं।

अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के मामले में पटना से अंकल जी गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बिहार से शुरू होकर उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी के मामले के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि पटना निवासी कमलकांत वर्मा उर्फ अंकल मामले में गिरफ्तार होने वाला 11वां आरोपी है। एनआईए की जांच में पता चला है कि कमलकांत ने हरियाणा और अन्य स्थानों के विभिन्न आग्नेयास्त्र कारखानों से अवैध रूप से गोला-बारूद खरीदने वाले गिरोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एजेंसी ने कहा कि गोला-बारूद की तस्करी उत्तर प्रदेश में की गई और वहां से इस बिहार और देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाया गया। कमलकांत की गिरफ्तारी एनआईए द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 23 स्थानों पर की गई छापेमारी के कुछ दिनों बाद हुई है, जिसके परिणामस्वरूप चार अन्य आरोपियों रवि रंजन, शशि प्रकाश, विजय कालरा और कुश कालरा को गिरफ्तार किया गया था। चार दिसंबर को की गई छापेमारी के दौरान कई हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किये गये थे।

नशीले कफ सिरप की कमाई से टेरर फंडिंग... हवाला ऑपरेटर्स की तलाश में जुटी ईडी

लखनऊ (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े बड़े सिंडिकेट की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों ने बताया कि इस नेटवर्क में करोड़ों रुपये के लेन-देन हवाला ऑपरेटर्स के जरिए किए जा रहे थे, जिनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी को आशंका है कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के बाद कफ सिरप की सप्लाई चेन कुछ इस्लामिक संगठनों के नियंत्रण में चली जाती थी, जहां से प्राप्त कमाई का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में किया जा सकता था। हालांकि, इस दिशा में ठोस सबूत जुटाने के लिए ईडी गहन जांच कर रही है। मामले में मेरठ निवासी आसिफ और वसीम के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं, जो भारत में तस्करी सिंडिकेट से जुड़े बताए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि दुबई में रह रहे आसिफ का भारत और बांग्लादेश के नेटवर्क से सीधा संपर्क था। वहां विदेश से ही ऑपरेशन को चलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। ईडी की टीम इस पूरे लिंक को मजबूत करने के लिए हवाला ऑपरेटर्स की कड़ियों को खंगाल रही है। साथ ही, कफ सिरप की एवज में बांग्लादेश से नकली भारतीय मुद्रा की सप्लाई के संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। यह मामला कोडीन आधारित कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी से जुड़ा है, जो नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होती है। सिंडिकेट फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों का सहारा लेकर दवा कंपनियों से सीधे माल खरीदता था और उस माल को सीमापार पहुंचाता था।

एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, कोच्चि में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

-सभी 160 यात्री सुरक्षित, वैकल्पिक फ्लाइट चलाने, की जा रही व्यवस्था

कोच्चि (एजेंसी)। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में गुरुवार को तकनीकी खराबी आने के बाद केरल के कोच्चि में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे एक बड़ा हवाई हादसा टल गया। फ्लाइट एआईई-398 जेद्दा से चली थी और कोझिकोड जा रही थी। रास्ते में पायलट को विमान के लैंडिंग गियर में दिक्कत महसूस हुई। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पायलट ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। संदेश मिलने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिए। जानकारी के मुताबिक विमान सुबह करीब 9.07 बजे सुरक्षित लैंड हुआ, जिसमें एहतियात के तौर पर रनवे पर फायर और रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। लैंडिंग के बाद विमान की जांच में पता चला कि उसके दो टायर फट गए थे, जिससे खराबी की गंभीरता की पुष्टि हुई और कोच्चि की ओर डायवर्ट करने के फ्लाइट क्रू के समय पर लिए गए फैसले को सही साबित किया। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि सभी इमरजेंसी सिस्टम चालू थे और योजना के अनुसार काम कर रहे थे। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट लाउंज में ठहराया गया है और उनकी आगे की यात्रा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।

सपा नेता की 14 करोड़ की संपत्ति कुर्क

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मानसिंह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न मामलों में दर्ज आरोपों के चलते उनके आवास और अन्य संपत्तियों को कुर्की किया जा रहा है। उनकी 14 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन लिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर आज गैंगेस्टर की होटल की संपत्ति को जिला प्रशासन की मौजूदगी मे कुर्क कर दिया गया। कार्रवाई के आदेश को चस्पा किया गया है। सपा नेता राजा मानसिंह सरियावा थाना पूरा कलंदर के निवासी हैं। उनके और उनकी पत्नी नीतू सिंह के ऊपर भी कार्रवाई हुई।

हसीना के बेटे ने चेताया कहा- कट्टर इस्लामिक देश बन रहा बांग्लादेश, भारत में बढ़ेगा आतंकवाद?

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजेब वाजेद जॉय ने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ढाका में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश को इस्लामिक शासन की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है और इससे भारत की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर पूछे गए सवाल पर जॉय ने कहा कि यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनके अनुसार, अवामी लीग की सरकार के दौरान भारत की पूर्वी सीमाएं आतंकवाद से सुरक्षित थीं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे पहले के दौर में बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत में विद्रोह और आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता था, और अब वह स्थिति दोबारा लौट सकती है।एक इंटरव्यू में 54 वर्षीय सजेब वाजेद जॉय ने कहा कि यूनुस सरकार जमात-ए-इस्लामी और अन्य इस्लामी पार्टियों को खुली छूट दे रही है और चुनाव में धांधली कराके इनको सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। वाजेद फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। यह इंटरव्यू ऐसे समय में सामने आया है जब भारत ने बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और भारतीय उच्चायोग को धमकी देने वाले चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताते हुए ढाका के उच्चायुक्त को तलब किया। दिल्ली में हालिया आतंकी गतिविधियों और बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय सेल के बीच संबंधों के सवाल पर जॉय ने कहा कि उन्हें यह जानकारी गोपनीय सुरक्षा सूत्रों से मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर फिर से सक्रिय हो चुके हैं, अल-कायदा के जाने-माने आतंकी वहां सक्रिय हैं और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों ने खुले मंचों से भाषण दिए हैं। उनके अनुसार, इससे भारत और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा तत्काल और वास्तविक है।

शेख हसीना के खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा के बाद दिए गए अपने बयानों को दोहराते हुए जॉय ने कहा कि बांग्लादेश तेजी से एक असफल इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार ने जमात-ए-इस्लामी और अन्य इस्लामिक दलों को खुली छूट दे दी है।

जॉय के मुताबिक, बांग्लादेश में इस्लामिक पार्टियों को कभी भी पांच प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिले हैं, लेकिन अवामी लीग और अन्य प्रगतिशील व उदारवादी दलों को चुनाव से बाहर रखकर एक धांधली भरा चुनाव कराया जा रहा है, ताकि इस्लामिक ताकतों को सत्ता में स्थापित किया जा सके।

भारत की भूमिका पर सवाल के जवाब में सजेब वाजेद जॉय ने कहा कि नई दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी के लिए ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जातीय पार्टी (जातीय पार्टी) को चुनाव से बाहर करना, आधे से ज्यादा मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने जैसा है। उनके अनुसार, ऐसे हालात में होने वाला चुनाव लोकतांत्रिक नहीं बल्कि पूरी तरह से धांधली भरा होगा। बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग किए जाने पर जॉय ने कहा कि किसी भी कानूनी प्रत्यर्पण के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में उनके खिलाफ मामलों में पूरी तरह से ड्यू प्रोसेस का अभाव रहा और उनकी मां को अपने वकीलों से संपर्क तक की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में, जॉय का मानना है कि भारत को इस मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

इंडिगो संकट पर संसदीय समिति सख्त, एयरलाइन और नियामक से 15 दिन में जवाब मांगा

नई दिल्ली। इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने के मामले को लेकर संसदीय समिति ने एयरलाइन और नागरिक उड्डयन नियामक के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। समिति के समक्ष पेश किए गए जवाबों को असंतोषजनक मानते हुए दोनों पक्षों को 15 दिन बाद दोबारा उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान उठाए गए अहम सवालों पर न तो एयरलाइन और न ही नियामक अधिकारी ठोस जवाब दे सके, जिससे समिति की चिंता और बढ़ गई। समिति की बैठक में इंडिगो की ओर से मुख्य परिचालन अधिकारी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नियामक संस्था की तरफ से शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा देश की अन्य प्रमुख एयरलाइनों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे। गौरतलब है कि 2 दिसंबर से देशभर में कई दिनों तक सैकड़ों उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, हजारों यात्री फंसे और वैकल्पिक व्यवस्था की कमी साफ नजर आई। बैठक की अध्यक्षता जदयू सांसद संजय झा ने की। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति इस मुद्दे पर किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। समिति ने फैसला किया कि उड़ानों के रद्द होने और उससे उपजी अव्यवस्था की जिम्मेदारी तय करने से पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, समिति ने बैठक में कई तीखे सवाल पूछे। सदस्यों ने जानना चाहा कि संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम लागू होने के बाद मंत्रालय और नियामक क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। यह भी सवाल उठाया गया कि क्या पायलटों की ड्यूटी व्यवस्था में बदलाव से छूट हासिल करने के उद्देश्य से एयरलाइन ने दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। इन सवालों पर एयरलाइन और नियामक के प्रतिनिधि स्पष्ट और संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे। समिति ने यह भी नाराजगी जताई कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए माफी मांगने के बजाय उड़ानों के रद्द होने का ठीकरा मौसम और तकनीकी कारणों पर फोड़ा गया। समिति का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर उड़ानों का रद्द होना केवल मौसम का परिणाम नहीं हो सकता। इसी वजह से चार सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट को निर्णायक माना जा रहा है, जिसके 28 दिसंबर तक सौंपे जाने की संभावना है।

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामला तकनीकी रूप से खारिज होने की कगार पर

-बीजेपी का पलटवार, उच्च न्यायालय ने गांधी परिवार को कोई क्लीन चिट नहीं दी

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक की राजनीति में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बढ़ती राजनैतिक बहस के बीच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने एक ओर केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का पलटवार किया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री शिवकुमार का दावा है कि नेशनल हेराल्ड मामला तकनीकी रूप से खारिज होने की कगार पर है, इसलिए दिल्ली पुलिस को दर्ज एफआईआर वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करने की एक रणनीति है। शिवकुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर्नाटक की महत्वपूर्ण योजनाओं (जैसे गृह लक्ष्मी, ऊपरी भद्रा परियोजना और मनरेगा) का पैसा जानबूझकर रोका है। शिवकुमार ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन का बचाव करते हुए अन्य राज्यों (विशेषकर महाराष्ट्र) से इसकी तुलना की। उन्होंने दावा किया कि पिछले 24 महीनों में सरकार ने अपने सभी चुनावी वादों को कुशलतापूर्वक पूरा किया है। उनके अनुसार, केंद्र के असहयोग के बावजूद राज्य की कल्याणकारी योजनाएं जारी हैं। वहीं कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों की आलोचना कर कहा कि उच्च न्यायालय ने गांधी परिवार को इस मामले में कोई राहत या क्लीन चिट नहीं दी है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जांच से बचने के लिए संवैधानिक निकायों को निशाना बना रही है और राज्य में अशांति का माहौल पैदा कर रही है।

पंजाब पंचायत चुनाव: जिला परिषद और ब्लॉक समिति में आप का दबदबा, विपक्ष को करारी शिकस्त

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के मतगणना परिणामों ने राज्य की राजनीति में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की मजबूत पकड़ को एक बार फिर उजागर कर दिया है। अब तक घोषित नतीजों के अनुसार आप ने दोनों ही स्तरों पर अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अंतिम परिणामों की आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है, लेकिन मौजूदा आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ग्रामीण राजनीति में भी आप का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मंगलवार को सभी मतगणना केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना प्रक्रिया पूरी कर ली गई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिहाज से अहम माना था, और नतीजों ने पार्टी की रणनीति को सफल साबित किया है।

जिला परिषद के कुल 346 जोनों के लिए चुनाव कराए गए थे, जिनमें से अब तक 177 जोनों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें आम आदमी पार्टी ने 98 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 22 सीटों पर उसके उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इस तरह घोषित नतीजों में आप के पास कुल 120 सीटें आ चुकी हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस को 27 सीटें और शिरोमणि अकाली दल को 21 सीटों से संतोष करना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा और सीपीआई (एम) अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई हैं। खडूर साहिब के एक जोन में वैध नामांकन न मिलने के कारण वहां चुनाव नहीं हो सका।

ब्लॉक समिति की कुल 2838 सीटों में से 352 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे, जबकि 2486 जोनों के लिए मतदान हुआ। अब तक 2097 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। इनमें आप ने 892 सीटों पर सीधी जीत हासिल की है और 339 सीटें निर्विरोध जीतकर कुल 1231 सीटों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस को 419 सीटों पर जीत और 3 निर्विरोध सीटों के साथ कुल 422 सीटें मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल को 253, भाजपा को 49 और बसपा को 26 सीटें हासिल हुई हैं। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने 116 सीटों पर जीत दर्ज की है।

अब तक के रुझानों से साफ है कि आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया है। विपक्षी दलों के लिए ये नतीजे चेतावनी के रूप में देखे जा रहे हैं, खासकर कांग्रेस और अकाली दल के लिए, जिनका परंपरागत आधार ग्रामीण क्षेत्रों में माना जाता रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अंतिम आंकड़े जारी होने के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी, लेकिन मौजूदा परिणामों ने पंजाब की राजनीति में आप के बढ़ते प्रभाव को मजबूती से रेखांकित कर दिया है।

मोदी सरकार चाहती... हमें घुटनों पर ला सकती थी, लेकिन इसके बदले हमारी पूरी मदद की

-उमर अब्दुल्ला का बयान विरोधी दलों के आरोप से अलग

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दो टूक कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ संबंधों का सामान्य होना फिलहाल 'असंभव' दिखाता है। उन्होंने आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी और इस्लामाबाद की ओर से राजनीतिक स्तर पर गंभीरता के अभाव को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया। एक कार्यक्रम में सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि संवाद ही किसी भी विवाद का अंतिम समाधान होता है, लेकिन बातचीत के लिए जिस अनुकूल माहौल की जरूरत होती है, वहां वर्तमान में पूरी तरह नदारद है। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसा माहौल बनाने की पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान की है।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने पहलगाम, दिल्ली और अन्य स्थानों पर हुए हालिया आतंकी हमलों का उल्लेख कर कहा कि जमीनी सच्चाई अब भी शत्रुतापूर्ण बनी हुई है। इसतहर के हालात में भारत से यह अपेक्षा करना कि वह उकसावों को अनदेखा करे, व्यावहारिक नहीं है। सीएम अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को 'शक्तिविहीन' बताकर कहा कि एक इसतरह के व्यक्ति के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसने कभी देश के सबसे सशक्त राज्यों में से एक का नेतृत्व किया हो और आज वह एक इसतरह के केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसके पास देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना में बेहद सीमित अधिकार हैं। उन्होंने उपराज्यपाल के निरंतर हस्तक्षेप की आलोचना कर केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध लक्ष्य तय करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार जरूर है, लेकिन कानून-व्यवस्था, पुलिस और नौकरशाही से जुड़े अहम फैसले अब भी उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके बाद सरकार की जवाबदेही और निर्णय लेने की क्षमता के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने माना कि जनता की अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची होती हैं, खासकर तब जब एक निर्वाचित सरकार सत्ता में आती है, लेकिन मौजूदा संवैधानिक ढांचे में सरकार की सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है।

जब सीएम उमर से पूछा गया कि क्या मोदी सरकार विपक्ष-शासित राज्यों के प्रति बदले की भावना से काम करती है, तब उमर अब्दुल्ला ने आम विपक्षी सोच से हटकर चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, 'अगर मोदी सरकार चाहती, तब हमें घुटनों पर ला सकती थी, लेकिन इसके उलट हमें तय बजट से ज्यादा धनराशि दी गई है।' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास प्रशासनिक और आर्थिक दबाव बनाने के कई तरीके हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनके अनुसार, कम से कम वित्तीय सहयोग के स्तर पर बदले की राजनीति नहीं हुई है। बता दें कि राजनीतिक हलकों में उमर का यह बयान केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के रिश्तों पर चल रही बहस में एक व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है।

मुस्लिम पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा या प्राणायाम करें तो इसमें क्या गलत है?

होसबोले ने कहा-भारतीय सांस्कृतिक जड़ें एक हैं, पूजा के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं

गोरखपुर (एजेंसी)। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा। अगर नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा या प्राणायाम करेंगे तो इसमें क्या गलत है? होसबाले ने बुधवार को कहा कि प्रकृति को अपनाना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और प्रकृति पूजा से जुड़ी प्रथाएं किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं हैं।

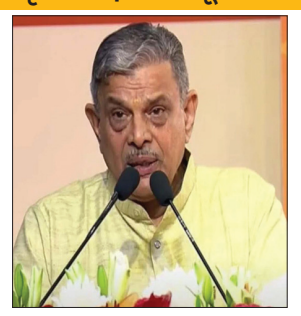

उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी भी व्यक्ति या समुदाय को अपना दुश्मन नहीं मानता और समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समावेशिता में विश्वास करता है। गोरखपुर के खोराबार मैदान में एक 'हिंदू सम्मेलन' को संबोधित करते हुए होसबाले ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से गहराई से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भी नदियों और पेड़ों की पूजा करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये परंपराएं प्रकृति संरक्षण और सामूहिक भलाई से जुड़ी हैं।

होसबाले ने आगे कहा कि इसे संकीर्ण धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य-उन्मुख अभ्यास है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है और इसे करने से कुछ भी नहीं खोता है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम ये करो तो वो पूजा छोड़ दो, नमाज़ छोड़ दो। ये तो हम नहीं कहेंगे। सांस्कृतिक एकता पर जोर देते हुए होसबाले ने कहा कि भारतीय संस्कृति धार्मिक सीमाओं से परे सह-अस्तित्व और प्रकृति के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आरएसएस समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी सम्मान और सद्भाव में विश्वास करता है। 'हिंदू-हिंदुत्व', 'राष्ट्र-राष्ट्रीयता', और 'भारत-भारतीयता' जैसे विषयों पर बोलते हुए होसबाले ने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल चरित्र निर्माण से ही संभव है। उन्होंने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक जड़ें एक हैं। पूजा के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक है- सनातन। धर्म जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया भर में मानवता के कल्याण के लिए मानवीय मूल्यों को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म को मानव धर्म बताया है। किसी भी देश के लोग इसका पालन कर सकते हैं। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव इसका एक स्पष्ट उदाहरण है।

बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायू पर एआईएमआईएम की नजर, साथ में लड़ेंगे चुनाव!

कोलकाता (एजेंसी)। बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायू कबीर पर एआईएमआईएम की नजरें टिक गई हैं। चूंकि हुमायू 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं और उन्हे लगने लगा है कि वे पश्चिम बंगाल में निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी मजबूती को एआईएमआईएम ने और मजबूत करने का प्रयास किया है। माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं।

एआईएमआईएम की पश्चिम बंगाल इकाई हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में दिखाई दे रही है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुक्रवार को निलंबित विधायक के साथ गठबंधन करने की इच्छा व्यक्त की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा कि कबीर के साथ बातचीत चल रही है, जो छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की नींव रखकर राजनीतिक बवाल खड़ा करने के बाद अल्पसंख्यकों की आवाज मुखरता से उठाने वाले एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने कबीर से पहले ही बात कर ली है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अगले साल के विधानसभा चुनाव में 'कुछ सीट' पर तालमेल की संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर असदुद्दीन ओवैसी की मजबूत पकड़ के कारण हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। हमारी भी कुछ चुनिंदा सीट पर गठबंधन की संभावना तलाशने में रुचि है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय हैदराबाद के सांसद का होगा।

तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए 5 करोड़ का चंदा आ चुका है। उन्होंने बताया कि यह पहले से ज्यादा ऊंची बनने वाली है। साथ ही उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि इसका मुर्शिदाबाद में कोई असर नहीं पड़ेगा। कबीर 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं।कबीर ने कहा, जहां वह मॉडल था, वहां से ज्यादा हाइट पर होगा, ज्यादा चौड़ा भी होगा। वो जो था उससे और ज्यादा 65 फुट ऊंचा होगा। उन्होंने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी थी। उन्होंने जानकारी दी, 5 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। और जो मटेरियल आया है, वो भी डेढ़-दो करोड़ रुपये का होगा।विधायक ने नई पार्टी के ऐलान को लेकर कहा, नई पार्टी का ऐलान 22 दिसंबर को दोपहर 12 से 1 बजे तक होगा। इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। खबरें थीं कि मस्जिद की नींव रखने के ऐलान से ममता बनर्जी नाराज थीं। हालांकि, टीएमसी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा था।